एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

सितंबर 2014
खंड XXVIII • अंक III

इस अंक में

4 कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, वियतनाम (सीएलएमवी) के साथ भारत के व्यापार संबंध
5 दक्षिण अफ्रीका : व्यापार संभावनाएं
6 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
7 भारत में पूंजीगत माल उद्योग
8 गत तिमाही
9 एक्ज़िम बैंक समाचार
10 भारत में नवीकरणीय ऊर्जा : संभाव्यता
11 एक्ज़िम बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार
12 एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 एक्ज़िम बैंक के ग्रिड कार्यकलाप
16 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
17 भारतीय व्यापार का प्रदर्शन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

पोत-निर्माण क्षेत्र का रणनीतिक विकास : भारत तथा चुनिंदा देशों में संस्थागत सहायता प्रणाली और नीतिगत ढांचा

वैश्विक व्यापार की प्रवृत्तियों के अनुरूप वैश्विक पोत-निर्माण उद्योग में भी वर्ष 2008 से 2012 की अवधि के दौरान लगातार संकुचन देखा गया. वैश्विक पोत-निर्माण के ऑर्डर बुक की स्थिति 2008 के कुल 368 मिलियन टन भार से घटकर वर्ष 2012 में 160 मिलियन टनभार रह गई (चार्ट). चीन, कोरिया, जापान, फिलीपीन्स, वियतनाम तथा भारत जैसे प्रमुख पोत निर्माण राष्ट्रों में इस उद्योग में गिरावट आयी.

तीन बड़े देश (बिग 3) अर्थात चीन, कोरिया और जापान वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में वर्ष 2013 में कुल 87 प्रतिशत हिस्से के साथ इस उद्योग में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं. हालिया वर्षों में फिलीपीन्स, ब्राजील तथा वियतनाम भी महत्वपूर्ण पोतनिर्माण राष्ट्र के रूप में उभरे हैं जो संबंधित देश की सरकार द्वारा मजबूत संस्थागत एवं नीतिगत सहायता प्रक्रिया का द्योतक है. वर्ष 2013 में फिलीपीन्स चौथे सबसे बड़े पोत निर्माता (2006 में आठवें स्थान से बढ़कर) के रूप में उभरा और ब्राजील अब पांचवां (2006 में 12वें स्थान से बढ़कर) सबसे बड़ा पोत निर्माता है.

लम्बे समय तक संकुचन के बाद उछाल के संकेत

तथापि वर्ष 2013 में वैश्विक व्यापार में हालिया वृद्धि को दर्शाते हुए वैश्विक पोतनिर्माण उद्योग ने भी उछाल दर्ज की है जो 2012 में 160 मिलियन टन भार से बढ़कर 2013 में 182.9 मिलियन टन भार के स्तर पर पहुंच गया है. भारत को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख पोत निर्माता देशों ने उद्योग में कायाकल्प दर्ज किया है.

भारतीय पोत निर्माण उद्योग तथा वैश्विक रैंकिंग

भारतीय पोत निर्माण 2006 में 0.8 मिलियन टन भार से 2008 में 3.5 मिलियन टन भार तक पहुंच गया जो 2009 में 3.4 मिलियन टन भार के स्तर पर बना रहा. तथापि उद्योग में उसके बाद निरंतर गिरावट आई और 2013 में 1.1 मिलियन टन भार के स्तर पर पहुंच गया. परिणामस्वरूप, वैश्विक पोतनिर्माण में भारत का हिस्सा जो 2006 में 0.4 प्रतिशत के मामूली स्तर से बढ़कर 2009 में 1.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया, उसके बाद लगातार गिरते हुए 2013 में 0.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था. वर्ष 2006 से 2009 के दौरान भारत की ऑर्डर बुक में तीव्र वृद्धि से प्रमुख पोत निर्माता देशों में भारत की रैंकिंग में भी सुधार हुआ (तालिका).

पोतों के निर्यात में भारत की वैश्विक क्षमता

पोतों तथा नौकाओं के प्रमुख वैश्विक निर्यातकों में भारत का अहम स्थान है. इस क्षेत्र में भारत की संभाव्यता को दर्शाते हुए भारत के निर्यात में वर्ष 2002 से 2011 की अवधि के दौरान सतत् तथा तीव्र वृद्धि दर्ज की गई जो इस अवधि में 56 मिलियन यूएस डॉलर के मामूली स्तर से बढ़कर 7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इसके परिणामस्वरूप, भारत का रैंक वर्ष 2002 के

चार्ट : वैश्विक पोतनिर्माण की प्रवृत्तियां : वर्ष 2006-2013 के अंत में ऑर्डर बुक की स्थिति

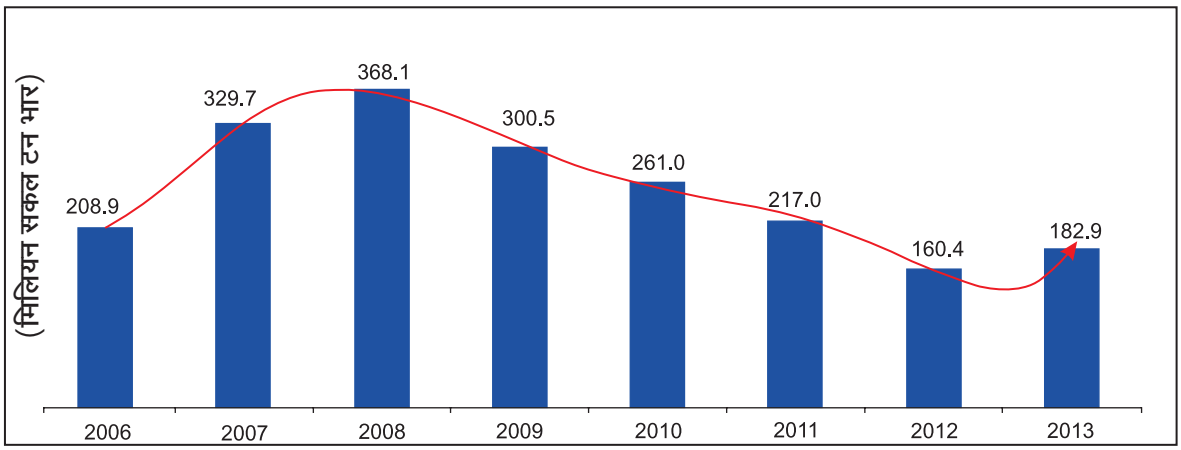

स्रोत : पोतनिर्माण सांख्यिकी, 2014, शिपबिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ जापान द्वारा, आईएचएस शिपबिल्डिंग सांख्यिकी के आधार पर

तालिका : वैश्विक पोतनिर्माण : वर्ष 2006–2013 के अंत में ऑर्डर बुक (विश्व टन भार में प्रतिशत हिस्सा)

रैंक		2006		2008		2009		2010		2013
	विश्व कुल	100.0	विश्व कुल	100.0	विश्व कुल	100.0	विश्व कुल	100.0	विश्व कुल	100.0
1	द. कोरिया	37.0	द. कोरिया	37.4	चीन	37.0	चीन	39.5	चीन	39.9
2	जापान	27.3	चीन	33.7	द. कोरिया	34.7	द. कोरिया	34.3	द. कोरिया	33.2
3	चीन	21.4	जापान	17.3	जापान	17.3	जापान	16.3	जापान	14.3
4	जर्मनी	2.0	फिलीपीन्स	1.6	फिलीपीन्स	2.2	फिलीपीन्स	2.7	फिलीपीन्स	2.6
5	ताइवान	1.1	वियतनाम	1.2	भारत	1.1	ब्राजील	0.9	ब्राजील	2.3
6	वियतनाम	1.0	भारत	1.0	वियतनाम	1.0	वियतनाम	0.9	ताइवान	1.1
7	इटली	1.0	जर्मनी	1.0	ब्राजील	0.7	भारत	0.9	वियतनाम	1.1
8	फिलीपीन्स	0.9	रोमानिया	0.9	ताइवान	0.7	ताइवान	0.7	रोमानिया	0.9
9	रोमानिया	0.8	ब्राजील	0.7	जर्मनी	0.7	जर्मनी	0.6	यूएस	0.7
10	भारत	0.4	ताइवान	0.7	इटली	0.7	इटली	0.5	इटली	0.6
11	यूएस	0.3	इटली	0.5	रोमानिया	0.6	रोमानिया	0.4	भारत	0.6
12	ब्राजील	0.1	यूएस	0.2	यूएस	0.2	यूएस	0.1	जर्मनी	0.6

स्रोत : पोतनिर्माण सांख्यिकीय, 2014, शिपबिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ जापान द्वारा, आईएचएस शिपबिल्डिंग सांख्यिकीय के आधार पर
नोट : पोत का आकार : 100 टनभार तथा इससे अधिक

22वें स्थान से वर्ष 2008 में 10वें स्थान और वर्ष 2009 में 5वें स्थान पर आ गया. अपनी वैश्विक निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2011 में कुल वैश्विक निर्यात में 3.7 प्रतिशत निर्यात के साथ चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है. हालांकि वैश्विक मांग में थोड़ी मंदी आने के कारण भारत का निर्यात भी वर्ष 2012 में 4.1 बिलियन यूएस डॉलर (वैश्विक हिस्से का 2.6 प्रतिशत और 5वां स्थान) और वर्ष 2013 के दौरान 3.6 बिलियन यूएस डॉलर (वैश्विक हिस्से का 2.5 प्रतिशत और 7वां स्थान) रहा.

पोत निर्माण तथा आर्थिक विकास

लम्बी तटीय सीमाओं वाले विश्व के कई देशों में सफल पोत-निर्माण उद्योग की उनके आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका रही है. पोतनिर्माण उद्योग राष्ट्रीय जीडीपी में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के अंशदान को बढ़ाता है. अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेवा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निर्भरता के अलावा इस क्षेत्र का अन्य अग्रणी उद्योगों जैसे इस्पात, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी तथा उपकरणों आदि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापक प्रभाव है. अधिकांश विनिर्माण अनुषंगी उद्योगों पर इसके बहुगुणक प्रभाव तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की अपनी क्षमता की बदौलत पोतनिर्माण उद्योग को मातृ उद्योग के रूप में भी जाना जाता है. कई देशों ने अपने पोतनिर्माण क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है जिसने ऐसे देशों में राष्ट्रीय आर्थिक विकास में उद्योग का योगदान बढ़ा है.

संस्थागत सहायता प्रणाली तथा नातिगत ढांचे

भारत में, पोतनिर्माण उद्योग के लिए प्रमुख नीतिगत सहायता व्यवस्था पोतनिर्माण सब्सिडी योजना, 2002 रही है. इस योजना में 30 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान है और इसमें निजी शिपयार्डों को भी कवर किया गया है. तथापि यह सब्सिडी योजना अगस्त 2007 में बंद कर दी गई. सब्सिडी योजना के अलावा, भारतीय पोतनिर्माण क्षेत्र करों तथा शुल्कों जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क तथा मूल्य योजित कर के अधीन है. हाल ही में, केन्द्रीय बजट 2014-15 में यह कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय पोतनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की जाएगी.

ब्राजील में, सरकार ने पोतनिर्माण उद्योग के वित्तपोषण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जो मर्चेंट मरीन फंड (एफएमएम) द्वारा निधिक और प्रमुख एजेंट तथा उधारदाता के रूप में ब्राजीलियाई विकास बैंक (बीएनडीईएस) द्वारा परिचालित है. एफएमएम मुख्यतः आयात पर कर तथा अनुतट मालभाड़ा, जिसे फ्रेट एडीशनल फॉर मर्चेंट मरीन रिन्यूवल (एएफआरएमएम) कहा जाता है, द्वारा संपोषित है. एफएमएम के माध्यम से पोत मालिक शिपयार्ड उत्पादन का वित्तपोषण करते हैं और अपने ऑर्डर देशी शिपयार्डों में देकर अत्यंत अनुकूल वित्तपोषण का भी फायदा उठा सकते हैं. ब्राजील में पोत निर्माण क्षेत्र का विकास सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी पेट्रोब्रास और उसकी समुद्री परिवहन शाखा ट्रान्सपेट्रो द्वारा संचालित है.

फिलीपीन्स में, सरकार शिपिंग विकास अधिनियम, 2004 के तहत शिपयार्डों तथा सुविधाओं के निर्माण, विस्तार, उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक शिपयार्ड उपकरणों तथा अन्य पूंजीगत उपकरणों एवं अतिरिक्त पुर्जों के आयात पर कर छूट सहित विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से इस उद्योग को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करती है. इसके अलावा, उद्योग को 'प्राथमिकता का दर्जा'

दिया गया है जिससे उद्योग को निवेश बोर्ड द्वारा कई निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो गए हैं.

मलेशिया में, दिसंबर 2011 में 'मलेशियन शिपबिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री स्ट्रेटजिक प्लान (एसबीएसआर) 2020' घोषित किया गया यह इस उद्योग के लिए मील का पत्थर है जिसमें 2 प्रतिशत वैश्विक पोतनिर्माण बाजार हिस्सा प्राप्त करना और साथ ही दक्षिण चीन महासागर अपतटीय मरम्मत बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना जैसे लक्ष्य शामिल हैं. मलेशिया में शिपिंग तथा पोतनिर्माण उद्योग को मिलने वाले प्रोत्साहनों में शिपिंग कंपनी के लिए 70 प्रतिशत आयकर छूट और मलेशियाई जहाजों पर कार्यरत व्यक्तियों को आयकर छूट तथा पोतनिर्माण एवं पोत मरम्मत के लिए 5 वर्षों तक आयकर छूट शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले बैंक पेम्बांगुनान मलेशिया बेरहाद (बीपीएमबी) को इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी तथा तेल एवं गैस के साथ समुद्री क्षेत्र में मध्यावधि से दीर्घावधि वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अधिदेश प्राप्त है. इसके अलावा, सरकार ने देश के समुद्री उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए अन्य स्थानीय साझेदारों के साथ रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से राष्ट्रीय शिपिंग कारोबार क्षेत्र को विकसित करने के लिए ग्लोबल मैरीटाइम वेंचर्स बेरहाद (जीएमवीबी), जो बीपीएमबी की सहायक संस्था है, की भी स्थापना की है.

वियतनाम में, पोत निर्माण उद्योग एक प्राथमिकता क्षेत्र है. तदनुसार, सरकार ने पुनर्निवेश के लिए कॉरपोरेट आयकर तथा पूंजी उपयोग कर का प्रतिधारण; कॉरपोरेट आयकर में छूट; औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन, देशी पोतनिर्माण उद्योग को संरक्षण; आयात कर छूट; तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को सुगम बनाने के लिए संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के रूप में उद्योग को कई प्रोत्साहन प्रदान किए हैं. अद्यतन मास्टर प्लान में देश के पोतनिर्माण उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता तथा शिपयार्डो एवं सहायक उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. इसके अलावा, 2010 की पुनर्संरचना योजना ने वियतनाम में पोत निर्माण तथा मरम्मत उद्योग को आधार उद्योग बनने के लिए वियतनाम शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप (विनाशिन) के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है.

प्रमुख रणनीतियां एवं सिफारिशें

भारत में पोत-निर्माण राष्ट्र के रूप में उभरने की जबरदस्त संभाव्यता निहित है. सुदृढ़ पोतनिर्माण उद्योग के आर्थिक लाभों को देखते हुए अनुकूल नीतिगत ढांचा तथा संस्थागत सहायता प्रणाली एक सशक्त पोतनिर्माण राष्ट्र के रूप में उभरने में भारत के प्रयासों में काफी सहायक सिद्ध होगी. इस दिशा में, ब्राजील, फिलीपीन्स तथा वियतनाम सहित कई देशों ने अपने यहां एक सुदृढ़ नीतिगत ढांचा तथा सहायता प्रणाली लागू की है जिसने एक सफल पोत निर्माता राष्ट्रों के रूप में इन देशों के उभार में काफी योगदान दिया है.

ऐसे देशों के अनुभवों से सीख लेकर भारत स्वयं के पोत-निर्माण उद्योग के विस्तार तथा विकास को गति दे सकता है. इस दिशा में विस्तृत रणनीतियों एवं सिफारिशों में निम्न शामिल हो सकते हैं :

➢ मरीन फंड की स्थापना तथा देशी पोत निर्माण को सहायता

ब्राजील द्वारा स्थापित मर्चेंट मरीन फंड (एफएमएम) को ब्राजील के एक प्रमुख पोतनिर्माण राष्ट्र के रूप में उभार के पीछे अक्सर एक सफल प्रयास माना गया है. ब्राजील 2013 में 5वां सबसे बड़ा पोत निर्माता देश रहा है, जबकि 2006 में यह 12वें स्थान पर था. इस फंड के अंतर्गत शिपिंग तथा पोतनिर्माण क्षेत्र को वित्तीय सहायता 2001 के लगभग 130 मिलियन यूएस डॉलर समतुल्य से बढ़कर 2011 में 1.26 बिलियन यूएस डॉलर हो गयी है. इसके अलावा, देशी शिपयार्डो द्वारा पोत निर्माण पर विशेष ध्यान के साथ पेट्रोब्रास विस्तार कार्यक्रम जैसे प्रोरेफैम, ईबीएन तथा प्रोमेफ के अंतर्गत देशी शिपयार्डों को सहायता से भी ब्राजील में इस उद्योग को आवश्यक गति मिली है.

➢ रणनीतिक उद्योग दर्जा प्रदान करना

विश्व में चौथे सबसे बड़े पोत निर्माता देश के रूप में उभरे फिलीपीन्स ने देशी जहाजरानी विकास अधिनियम, 2004 के जरिए जहाजरानी तथा पोतनिर्माण उद्योग पर प्रोत्साहनकारी उपाय लागू किए हैं. इसके अलावा, पोतनिर्माण उद्योग पर सरकार के जोर को 2006 के एक आदेश से भी आंका जा सकता है जिसमें निवेश बोर्ड की निवेश प्राथमिकता योजना (आईआईपी) के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन प्रदान कर देशी पोतनिर्माण उद्योग को 'पॉयनियर उद्योग' का दर्जा प्रदान किया है.

➢ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन

प्रमुख पोतनिर्माण कंपनियों / शिपयार्डों के साथ संयुक्त उद्यम पोतनिर्माण उद्योग में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है. उदाहरण के लिए हुंडई विनाशिन शिपयार्ड, जो वियतनाम के विनाशिन तथा हुंडई मिपो डॉकयार्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है तथा अब अत्याधुनिक और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक सबसे बड़ा जहाज मरम्मत यार्ड माना जाता है.

➢ विशेषीकृत मरीन वित्तपोषण संस्था तथा विशिष्ट मरीन वित्त योजना

विशेषीकृत मरीन वित्तपोषण संस्था तथा विशिष्ट मरीन वित्तपोषण योजना की स्थापना भी पोत निर्माण उद्योग को बहु प्रतीक्षित प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है. मलेशिया में, पोतनिर्माण तथा मरम्मत उद्योग के लिए देश की रणनीतिक योजना 2020 के अनुरूप, बैंक पेम्बांगुनान मलेशिया बेरहाद (बीपीएमबी) देशी शिपयार्डों को मरीन वित्त योजना के माध्यम से मध्यावधि तथा दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान कर पोतनिर्माण उद्योग को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता है.

➢ विदेशी बाजारों से संभावित मांगों का पता लगाना

भारत के पोतनिर्माण कार्यकलापों तथा भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति उभरते बाजारों में जहाजों की मांग के अनुरूप भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है. इस हेतु अफ्रीका में विशिष्ट बाजारों की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है जो प्रमुख आयातक हैं.

इस दिशा में, अफ्रीका में संभावित बाजारों के लिए ऋण-व्यवस्थाएं लागू करना एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है. इससे इन देशों को भारत से आयात बढ़ाने में सहायता मिलेगी और साथ ही भारतीय शिपयार्डों के लिए सुनिश्चित ऑर्डर भी मिल सकेंगे. उदाहरण के लिए, चीनी एक्ज़िम बैंक ने चीन में देशी शिपयार्डों का निर्माण तथा निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में सहायता के लिए ईथियोपिया, ब्राजील तथा ईरान में शिपिंग कंपनियों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.

4 कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, वियतनाम (सीएलएमवी) के साथ भारत के व्यापार संबंध

वर्ष 1992 में भारत द्वारा 'लुक ईस्ट पॉलिसी' लागू की गई जो आसियान देशों (कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, वियतनाम - सीएलएमवी सहित) के साथ व्यापक आर्थिक तथा रणनीतिक संबंध विकसित करने की दिशा में एक पहल थी. तभी से भारत ने इन देशों के साथ एक वार्ता साझेदार से रणनीतिक साझेदार की वर्तमान हैसियत के रूप में प्रगति की है.आर्थिक तथा व्यापार संबंध, जिनसे व्यापार मात्रा में वृद्धि हुई है, गहन आर्थिक विनियोजन का परिचायक है. पिछले दस वर्षों के दौरान सीएलएमएमवी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 2004 के 1.1 बिलियन यूएस डॉलर से नौगुने से अधिक बढ़कर 2013 में 11.2 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है (**चार्ट**). व्यापार संतुलन 2013 में 2.6 बिलियन यूएस डॉलर के अधिशेष के साथ भारत के पक्ष में है. सीएलएमवी देशों में म्यांमार तथा लाओ पीडीआर के साथ भारत का व्यापार घाटा है. सीएलएमवी देशों को भारत के निर्यात में औषधियां, मशीनें एवं उपकरण, रेलवे से इतर वाहन, प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुएं और कपास शामिल हैं. दूसरी ओर क्षेत्र से भारत के प्रमुख आयात में रबड़ तथा उसकी वस्तुएं, लकड़ी (भस्म) तथा लकड़ी की वस्तुएं, अयस्क, स्लैग तथा भस्म, खनिज ईंधन, तेल एवं आसवन उत्पाद तथा कॉफी, चाय तथा मसाले शामिल हैं.

कंबोडिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है यह बढ़ते निर्यात के चलते 2004 के 17 मिलियन यूएस डॉलर से आठ गुने से अधिक बढ़कर 2013 में 149.6 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार व निर्यात में कंबोडिया का हिस्सा क्रमशः 0.2 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत है जबकि आसियान क्षेत्र से भारत के आयात में इसका नगण्य हिस्सा है. संरचनात्मक रूप से, भारत का कम्बोडिया के साथ व्यापार अधिशेष है.

लाओ पीडीआर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2004 के 1 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 172.6 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है. व्यापार संतुलन, जो अभी तक भारत के पक्ष में है, 2010 में लाओ पीडीआर के पक्ष में आ गया जिसकी मुख्य वजह लाओ पीडीआर से तांबा अयस्क तथा सांद्रणों की भारत द्वारा अधिक मात्रा में खरीद रही है. 2009 में भारत ने लाओ पीडीआर सहित अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान योजना (डीएफटीपी) की सुविधा प्रदान की. यह योजना लाओस को भारत के कुल टैरिफ के 94 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करती है.

नब्बे के दशक के प्रारंभ से लुक ईस्ट पॉलिसी (एलईपी) के अंगीकरण से भारत और म्यांमार के बीच संपर्क लगातार बढ़ रहा है. भारत और म्यांमार के बीच व्यापार संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जिससे भारत का व्यापार 2004 के 523.4 मिलियन यूएस डॉलर से चार गुना बढ़कर 2013 में 2 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है. 2013 में म्यांमार के वैश्विक निर्यात में भारत का 13 प्रतिशत हिस्सा रहा और यह इसका तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. तथापि, म्यांमार से दालों और वन आधारित उत्पादों के बढ़े हुए आयात के कारण भुगतान संतुलन म्यांमार के पक्ष में है. दोनों देशों ने 2015 तक के लिए 3 बिलियन यूएस डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है.

भारत और सीएलएमवी देशों (म्यांमार के माध्यम से) के बीच सीमा-पार व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और भारत तथा म्यांमार के बीच 1643 किमी की सीमा के साथ भौगोलिक निकटता के चलते द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की विपुल संभाव्यता है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के चार राज्य अर्थात् मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर करते हैं. म्यांमार सीमा व्यापार विभाग के अनुसार, भारत और म्यांमार के बीच व्यापार टर्नओवर 10 से 22 मिलियन यूएस डॉलर के बीच है जो अनौपचारिक व्यापार को शामिल करने पर और अधिक हो सकता है (भारतीय दूतावास, यांगून). अन्य रिपोर्टें भी सीमा के जरिए भारत से म्यांमार को उर्वरक, वाहन, विशेषकर दुपहिया वाहन जैसी मदों के अनौपचारिक व्यापार की संभाव्यता दर्शाती हैं.

हाल के वर्षों में वियतनाम भारत संबंधों में तेजी आई है और कई आर्थिक तथा वाणिज्यिक करार हुए हैं. भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2004 के 608.1 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2013 में 8.8 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. दोनों पक्षों ने 2015 तक 7 बिलियन यूएस डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है. वियतनाम ने 1 जून, 2010 से भारत-आसियान एफटीए की अभिपुष्टि की है. सेवाओं तथा निवेश में व्यापार पर प्रस्तावित इस करार से द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिल सकता है. सीएलएमवी क्षेत्र में वियतनाम भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार और आयात स्रोत है.

चार्ट : सीएलएमवी देशों के साथ भारत का व्यापार

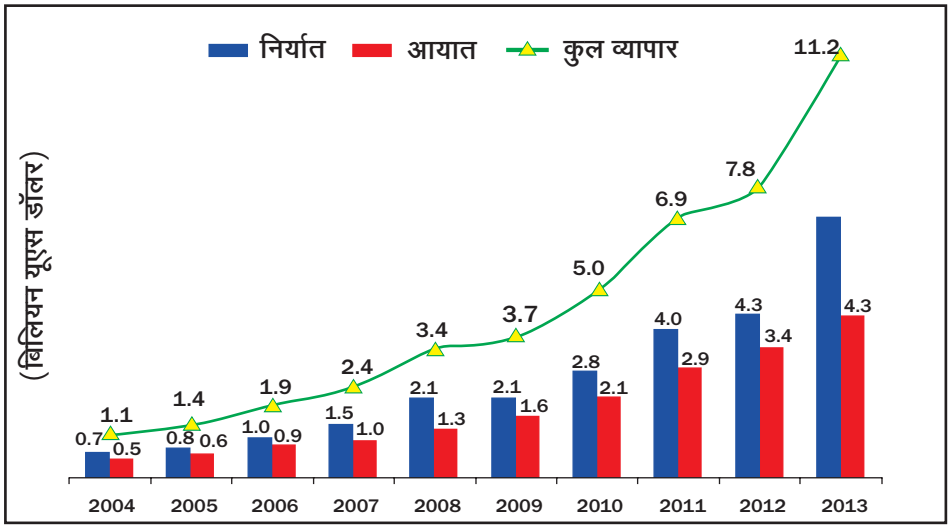

स्रोत : ट्रेड मैप, आईटीसी

अफ्रीकी महाद्वीप के शीर्ष पर रणनीतिक रूप से स्थित दक्षिण-अफ्रीका निवेश के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य स्थान है.

दक्षिण अफ्रीका में निवेश की विपुल संभाव्यता है. एक मजबूत उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक विकसित आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला एक अनोखा देश है.

दक्षिण अफ्रीका में कारोबार करने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

➢ सुदृढ आर्थिक नीतियां

दक्षिण अफ्रीका के अनुशासित राजकोषीय ढांचे का उद्देश्य देशी प्रतिस्पर्धा, वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था की बाह्य उन्मुखता को बढ़ाना है. प्रमुख आर्थिक सुधारों से आर्थिक स्थिरता उच्च स्तर तक बढ़ी है. कर कम कर दिए गए हैं, टैरिफ घटा दिया गया है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाया गया है, और विदेशी मुद्रा नियंत्रण में ढील दी गई है.

उज्ज्वल संभावनाओं के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका को भी गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता से जूझना पड़ रहा है. सरकार दो प्रमुख आर्थिक ढांचों के माध्यम से इनका समाधान कर रही है. पहला है-नया वृद्धि पथः जिसका लक्ष्य अधिक विकसित तथा साम्य अर्थव्यवस्था का सृजन करना है; और दूसरा है- औद्योगिक नीति कार्यवाई योजनाः जिसका लक्ष्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देना है.

दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों के अच्छे नतीज़े आए हैं. वास्तविक ब्याज दर स्थिर हो गई है और मुद्रा प्रतिस्पर्धी दरों पर बनी हुई है.

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण अफ्रीका में विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा.

➢ अनुकूल कानूनी तथा कारोबारी वातावरण

लेन-देनों तथा वाणिज्यिक करारों से संबंधित सामान्य वाणिज्यिक नियम और पद्धतियां सामान्यतः वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा प्रथाओं के अनुरूप हैं.

व्यापार तथा उद्योग को मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर शामिल किया जाता है. न्यायालयों का द्वार ठीक उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर विदेशियों के लिए खुला है जो दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिए हैं. यद्यपि कई वाणिज्यिक विवाद पक्षकारों के बीच करारों द्वारा विवाचन के माध्यम से निपटाए जाते हैं.

जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (जेएसई लिमिटेड) बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष 20 स्टॉक एक्सचेंजों में स्थान रखता है. इसने अपनी सूचीबद्धता अपेक्षाओं, प्रकटनों तथा निरंतरता दायित्वों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसएलई) के अनुरूप तैयार किया है और निवेशकों को संरक्षण प्रदान करता है.

➢ विश्व-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर

दक्षिण अफ्रीका के पास आधुनिक परिवहन नेटवर्क, दूर-संचार सुविधा तथा व्यापक रूप से उपलब्ध ऊर्जा परिष्कृत सहित विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है.

सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देने तथा रोजगार का सृजन करने के लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को चिन्हित किया है.

➢ बाजारों तक पहुंच

अफ्रीकी प्रांत के दक्षिणी अग्रभाग पर स्थित दक्षिण अफ्रीका 14 देशों तक पहुंच के लिए आदर्श स्थिति में है जिनमें दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) तथा अफ्रीकी पूर्वी तट के द्वीपसमूह और खाड़ी के देश तथा भारत भी शामिल है. दक्षिण अफ्रीका मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के उभरते बाजारों और दक्षिण एवं सुदूर पूर्व एशिया के नव औद्योगिकीकृत राष्ट्रों के बीच एक ट्रांस शिपमेंट बिन्दु है.

प्रमुख शिपिंग पथ भी दक्षिण अटलांटिक तथा हिंद महासागर में दक्षिण अफीकी समुद्री तटों से गुजरते हैं. इसके सात वाणिज्यिक पोर्ट महाद्वीप में सबसे बड़े, सुसज्जित तथा अत्यधिक कार्यकुशल नेटवर्क हैं.

➢ व्यापार सुधार , रणनीतिक गठजोड़

दक्षिण अफ्रीका के 200 से अधिक देशों तथा क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध हैं. इसे 2011 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के समूह ब्रिक में शामिल किया गया (जिसे अब ब्रिक्स कहते हैं).

दक्षिण अफ्रीकी सीमाशुल्क संघ (बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो तथा स्वीजीलैंड), दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय और यूरोपीय संघ के साथ इसके विशेष संबंध हैं. मोजाम्बिक तथा जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय करार भी किए गए हैं.

➢ दक्षिण अफ्रीका में कारोबार सुगमता

दक्षिणअफ्रीका विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2014 में 189 देशों की सूची में 43वें स्थान पर है. यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो कानूनी तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कारोबार के लिए समय, लागत तथा जटिलताओं की माप करता है.

➢ औद्योगिक क्षमता, श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी

देश का विनिर्माण उत्पादन निरंतर प्रौद्योगिकी-गहन होता जा रहा है, उच्च प्रौद्योगिकी गहन विनिर्माण क्षेत्रों जैसे मशीनें, वैज्ञानिक उपकरण तथा मोटर वाहन का कुल विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा बढ़ रहा है.

➢ प्रतिस्पर्धात्मकता

दक्षिण अफ्रीका को 2014-15 के लिए विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 144 देशों में 56वें स्थान पर रखा गया. यह उप-सहारन अफ्रीका में सर्वाधिक रैंकिंग वाला देश है और ब्रिक्स देशों में तीसरा स्थान रखता है.

सरकार ने मूल्य योजित विनिर्माण परियोजनाओं को प्रोत्साहन तथा औद्योगिक नवोन्मेष के लिए सहायता, वित्त तक आसान पहुंच और छोटे कारोबार के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराया है.

प्रमुख बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के निकट औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना की गई है जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमाशुल्क सहायता और कराधान में छूट की सुविधा प्रदान करते हैं.

दक्षिण अफ्रीका में व्यापार महौल उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों पर आधारित, सुविकसित तथा विनियमित है. प्रतिस्पर्धा कानून यूरोपीय संघ, यूएस तथा कनाडियाई मॉडलों पर आधारित हैं.

(यह लेख अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के सौजन्य से है).

स्रोत : www. southafrica.info

6 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

भारतीय एक्ज़िम बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है. एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सरकारी और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना, परियोजना, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं. इनके अंतर्गत भारतीय निर्यातक शिपिंग दस्तावेज के आधार पर एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान दायित्व रहित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं. एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. भारत सरकार के आदेश पर जारी ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवा भारत से लिया जाए. वर्तमान में एक्ज़िम बैंक की 197 ऋण-व्यवस्थाएं परिचालन में हैं जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप तथा सीआईएस के 74 देशों में 10.58 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण राशि अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश पर और उनके सहयोग से जुलाई-सितंबर 2014 तिमाही के दौरान निम्नलिखित पांच ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

➢ वियतनाम सरकार को भारत से उपकरणों / आपूर्तियों की खरीद के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने इसके पहले टेक्सटाइल मशीनों, जल विद्युत परियोजना, नाम चीन हाइड्रो पावर परियोजना के लिए उपकरणों एवं सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए वियतनाम सरकार को 91.50 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.

➢ सिनेगल में चावल स्वनिर्भरता कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए सेनेगल गणराज्य को 62.95 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक ने इसके पहले सिनेगल को ग्रामीण लघु उद्यमों के विकास तथा कृषि मशीनरी एवं उपकरण की खरीद, बसों एवं पिक-अप वैन के निर्यात,सिंचाई परियोजना, आई टी प्रशिक्षण परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा मत्स्य विकास परियोजनाओं के लिए कुल 199.33 मिलियन यूएस डॉलर की दस ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं.

➢ बांको एक्सटेरियर द क्यूबा, क्यूबा सरकार को दो ऋण-व्यवस्थाएं क्यूबा में थोक मिश्रण उर्वरक प्लांट के लिए 2.71 मिलियन यूएस डॉलर तथा हवाना में इंजेक्टेबल उत्पाद संयत्र के आधुनिकीकरण के लिए 5.05 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाएं. कुल 7.76 मिलियन यूएस डॉलर की उपर्युक्त दो ऋण–व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक ने अभी तक भारत सरकार के निर्देश पर क्यूबा को तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं जिससे प्रदान की गई ऋण–व्यवस्थाओं का कुल मूल्य 12.76 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है. क्यूबा सरकार को पहली ऋण-व्यवस्था क्यूबा के कैमाग्वे प्रांत में मिल्क पाउडर प्रोसेसिंग प्लांट के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड,
मुंबई : 400 005
फोन :+91-22-22172310
फैक्स : +91-22-22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ाने पर एक्ज़िम बैंक का विशेष जोर रहा है. भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बीसी-एनईआईए) कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण की शुरुआत से इसे बढ़ावा मिला है. बीसी-एनईआईए एक अनोखी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित वित्तपोषण का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है और पारंपरिक बाजारों तथा विकासशील देशों में नये बाजारों, जिन्हें मध्यावधि या दीर्घावधि आधार पर आस्थगित ऋण की जरूरत होती है, में प्रवेश के लिए एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में कार्य करती है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक्ज़िम बैंक के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की प्रायोगिक योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी की है. योजना के बारे में प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश मार्च 2013 में अनुमोदित किए जा चुके हैं.

वर्तमान में, ईसीजीसी द्वारा 51 देशों की एक सूची तैयार की गई है जिनके लिए भारतीय निर्यातक एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण ले सकते हैं. अन्य देशों से परियोजनाओं के लिए ऋण अनुरोध प्राप्त होने पर इस सूची को विस्तारित / संशोधित किया जाएगा. बैंक ने अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2.78 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 12 परियोजनाओं के लिए कुल 1.52 बिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की है. बैंक ने कई परियोजनाओं को सहायता देने के लिए सिद्धांत रूप में भी सहमति दी है. बीसी-एनईआईए के अंतर्गत वर्तमान सक्रिय पाइप लाइन में कई अग्रणी भारतीय परियोजना निर्यातकों की कुल 6.4 बिलियन यूएस डॉलर की 54 परियोजनाएं शामिल हैं.

पूंजीगत माल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है. समग्र आर्थिक वृद्धि पर भी इसका काफी प्रभाव है क्योंकि यह महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रदान कर भारत के भीतर मूल विनिर्माण विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है.

भारतीय पूंजीगत माल उद्योग का कार्य-निष्पादन हाल के वर्षों में कमजोर रहा है. वर्ष 2010-11 के दौरान पूंजीगत माल उद्योग 2009-10 के दौरान 1 प्रतिशत की सपाट वृद्धि की तुलना में 15 प्रतिशत की तीव्र गति से बढा. तथापि इस प्रदर्शन को 2011-12 में बरकरार नहीं रखा जा सका और पूंजीगत माल उद्योग के उत्पादन में वस्तुतः (-) 4.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. यह कमजोर प्रदर्शन 2012-13 तथा 2013-14 में भी जारी रहा और उद्योग में क्रमशः (-)6.3 प्रतिशत और (-) 3.8 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष गिरावट दर्ज की गई. **(चार्ट)**.

वर्ष 2012 के दौरान पूंजीगत माल का सबसे बड़ा निर्यातक (विश्व निर्यात में 19 प्रतिशत हिस्से के साथ) चीन था. उसके बाद जर्मनी (12 प्रतिशत), यूएसए (10 प्रतिशत), जापान (8 प्रतिशत), इटली (4 प्रतिशत) तथा हांगकांग (4 प्रतिशत) का स्थान रहा. पूंजीगत माल के कुल विश्व निर्यात में 0.6 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत 28वें स्थान पर रहा. प्रमुख आयातक यूएसए (15 प्रतिशत), चीन (10 प्रतिशत), जर्मनी (7 प्रतिशत), हांगकांग (4 प्रतिशत), यूके (4 प्रतिशत) तथा फ्रांस (4 प्रतिशत) रहे. भारत कुल विश्व आयात में 2 प्रतिशत हिस्से के साथ 17वें स्थान पर रहा.

देश में पूंजीगत माल की मांग में सतत वृद्धि हो रही है, किन्तु देशी विनिर्माता मांग से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ रहे हैं, जिससे विभिन्न बाजार खंडों में आयात पर निर्भरता बढ़ी है. यह इस क्षेत्र में देश के भारी व्यापार घाटे से प्रदर्शित होता है. 2013-14 में पूंजीगत माल का निर्यात गत वर्ष के 15.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 16.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. दूसरी ओर आयात में (-) 11.5 प्रतिशत की गिरावट आयी जो 2012-13 के 43.4 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2013-14 में 38.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. वर्ष 2013-14 में भारत के पूंजीगत माल के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य स्थानों में यूएसए (13.5 प्रतिशत), जर्मनी (5.4 प्रतिशत), यूएई (5.3 प्रतिशत), यूके (4.4 प्रतिशत) तथा 3.4 (प्रतिशत) शामिल हैं. पूंजीगत माल के लिए भारत के प्रमुख आयात स्रोतों में चीन (31.4 प्रतिशत), जर्मनी (12.1 प्रतिशत), यूएसए (8.7 प्रतिशत),जापान (8.5 प्रतिशत) तथा दक्षिण कोरिया (5.5 प्रतिशत) शामिल हैं.

चार्ट : पूंजीगत माल सूचकांक तथा सामान्य आईआईपी सूचकांक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

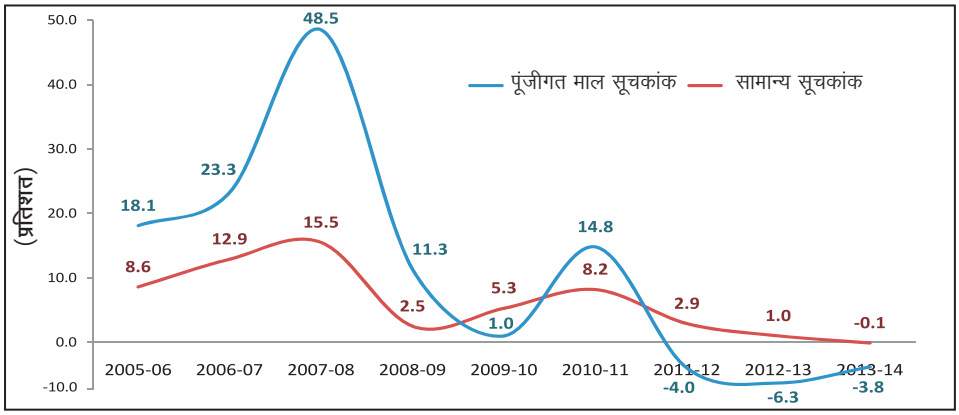

स्रोत : एमओएसपीआइ

बढ़ता आयात और देशी अर्थव्यवस्था में न्यून क्षमता, मुख्यतः न्यून शुल्क संरचना तथा आयात अनुकूल ईसीबी नीतियों के कारण है. पूंजीगत माल के उत्पादन के लिए कच्चे माल पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक सीमा शुल्क लगता है. इसके अलावा, शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन-पूर्व, उत्पादन तथा उत्पादनोत्तर चरण के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति है. ईसीबी निधियों और देशी निधियों के बीच लागत अंतर लगभग 1 से 2 प्रतिशत आता है. ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार, ईसीबी निधियों का देशी पूंजीगत माल की खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है, किंतु उधारकर्ता को ऋण रजिस्ट्रेशन नंबर (एलआरएन) के लिए आवेदन करते समय ऐसी स्थानीय खरीद के लिए अपेक्षित राशि की पहले ही घोषणा करनी होगी और भारत में प्राधिकृत डिपॉजिटरी के पास अपने रुपया खाते में राशि का तुरंत प्रत्यावर्तन करना होगा. दूसरी ओर, विदेशी मुद्राओं (या पूंजीगत माल के आयात) में प्रयोग के लिए ईसीबी को विदेशों में निर्धारित एजेंसियों के पास पार्क किया जा सकता है. ऐसी नीतियां देशी पूंजीगत माल उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाती हैं.

पूंजीगत माल क्षेत्र को अधिकांश मांग विनिर्माण क्षेत्र से प्राप्त होती है. विनिर्माण क्षेत्र का कार्य-निष्पादन , क्षेत्र के अधिकांश खंडों में व्यापार घाटे के साथ सामान्य रहा. इसके अलावा, भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अन्य समकक्षी देशों की तुलना में अभी भी कम है. तथापि, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के भारत सरकार के फोकस तथा विजन को देखते हुए क्षेत्र के आगे बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश है. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर देकर इसे और बढ़ावा दिया गया है.

आर एंड डी एवं नवोन्मेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, रणनीतिक अधिग्रहण, क्लस्टर विकास दृष्टिकोण, एसएमई के लिए निवेश सीमा के पुनर्निर्धारण और प्रौद्योगिकी गहन पूंजीगत माल क्षेत्र में संकेन्द्रित निवेश जैसे कदमों को शामिल करते हुए चुनिंदा रणनीतियां आगे चलकर इस क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होंगी.

समग्र रूप में कह सकते हैं कि भारत में पूंजीगत माल उद्योग के लिए भावी संभावनाएं विशेषकर मध्यावधि तथा दीर्घावधि में उज्ज्वल हैं. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए पूंजीगत माल एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 के 312,557 करोड़ रुपये से बढ़कर 2016-17 तक 681,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है.

एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक का गठन

भारत ने चीन आधारित एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के लिए 20 अन्य देशों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए. एआईआईबी बैंक का उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता करना और पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व बैंक तथा आईएमएफ पर निर्भरता कम करना है. इस करार पर ऊषा टिटुस, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए. एआईआईबी 2014 में गठित ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) विकास बैंक से पृथक बैंक होगा. बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा. बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से होगा और बैंक शीघ्र ही अपने परिचालन प्रारंभ करेगा.

सरकार ने निर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति दी

भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्माण क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अंतर्गत100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाएगी. निर्माण परियोजना में एफडीआई के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल आवश्यकता को 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 20,000 वर्गमीटर तथा परियोजनाओं के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को भी 10 मिलियन यूएस डॉलर से घटाकर 5 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया है. तथापि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी संस्था को एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी जो रियल एस्टेट कारोबार, फार्महाउसों के निर्माण तथा अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में लगी है या लगने वाली है.

स्वर्ण आयात में उछाल से सितंबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़ा

सोने के उच्चतर आयात और निर्यात में नरमी के चलते भारत का व्यापार घाटा सितंबर 2014 में 14.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो सितंबर 2013 में दर्ज किए गए 6.1 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे से 132.7 प्रतिशत अधिक है. वाणिज्य मंत्रालय का कहना है, ``व्यापार घाटे में यह उल्लेखनीय वृद्धि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के बिना आयातों में वृद्धि के कारण है''. सितंबर 2014 में भारत का समग्र पण्य निर्यात 28.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो सितंबर 2013 के दौरान 28.1 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग 2.7 प्रतिशत अधिक है. तथापि, महीने में भारत का आयात बढ़कर 43.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो सितंबर 2013 में 34.3 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है. 2014 में आयात मुख्यतः भारत के गैर-तेल आयात में वृद्धि के कारण बढ़ा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, सितंबर 2014 में सोने तथा अयस्क के आयात में असामान्य वृद्धि हुई. धात्विक अयस्क तथा अन्य खनिजों का आयात सितंबर 2014 में 8 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 105.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सोने का आयात बढ़कर लगभग 3.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो सितंबर 2013 से लगभग 450 प्रतिशत और अगस्त 2014 में 2 बिलियन यूएस डॉलर के सोने के आयात से 87.5 प्रतिशत अधिक है. अनुमान है कि भारत में सोने की मांग त्योहारी मौसम तथा कम कीमतों के कारण ऊंची बनी रहेगी.

भारत ने डब्ल्यूटीओ नियमों में खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान की वकालत की

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा है कि विकासशील देशों को 'प्रतिबंधों की धमकी के बिना' गरीबों का भरण-पोषण करने के लिए खाद्य भंडार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और डब्ल्यूटीओ नियमों में आवश्यक परिवर्तनों के साथ खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान अनिवार्य है. `स्थूल आर्थिक नीतिगत प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास' पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में यूएन में भारतीय मिशन के कांसुलर अमित नारंग ने कहा, ``खाद्य सुरक्षा का मुद्दा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास का केन्द्र बिन्दु है और इसे उसी अत्यावश्यकता से निरूपित किया जाना चाहिए जैसे अन्य मुद्दे किए जाते हैं.'' उन्होंने कहा कि भारत ने दिसंबर 2013 में बाली में डब्ल्यूटीओ के नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सक्रिय रूप से तथा `सद्विश्वासपूर्वक' भाग लिया है तथा देश व्यापार सुगमीकरण पर निर्णयों सहित बाली निर्णयों के प्रति वचनबद्ध है.

एफटीए की समीक्षा लगभग पूरी हुई : सीतारामन

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय प्रेस ट्रस्ट से कहा कि विभिन्न देशों के साथ भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) की समीक्षा प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और देशी विनिर्माताओं को संशोधित समझौतों से फायदा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि `हमने एफटीए और सेज की समीक्षा की है तथा प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है. ऐसा मानना है कि कुछ एफटीए करारों से साझेदार देशों को फायदा हो रहा है और इस संबंध में वित्त एवं उद्योग मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है. वाणिज्य मंत्रालय में हम देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करारों का बेहतर उपयोग चाहते हैं तथा सरकार इसे सुनिश्चित करेगी.' सीतारामन ने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ एफटीए के लिए इच्छुक है.

एस एंड पी ने भारत की आउटलुक रेटिंग 'निगेटिव' से बढ़ाकर 'स्टेबल' की

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने यह कहते हुए कि देश में सरकार के लिए जनादेश तथा राजनीतिक स्थिरता सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करती है, भारत की ``बीबीबी'' रेटिंग के लिए आउटलुक `निगेटिव' से बढ़ाकर `स्टेबल' कर दिया है. एस एंड पी ने अप्रैल 2014 में भारत के लिए आउटलुक घटाकर `निगेटिव' कर दिया था. भारत को अब `स्टेबल' आउटलुक के साथ न्यूनतम निवेश ग्रेड की रेटिंग दी जाती है.

यूएसए में भारतीय निवेश को बढ़ाने के लिए सेलेक्ट यूएसए के साथ सहयोग

एक्ज़िम बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेलेक्ट यूएसए के साथ एक आशय ज्ञापन (एमओआई) पर हस्ताक्षर किए. सेलेक्ट यूएसए अमेरिकी सरकार का ऐसा पहला व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य यूएसए में कारोबारी निवेश को बढ़ावा देना है. एक्ज़िम बैंक संयुक्त राज्य सहित अन्य साझेदार देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को सहयोग प्रदान करने में सक्रिय रूप में शामिल है. भारत की नई सरकार के साथ अमेरिका के बढ़ते संबंधों की दृष्टि से यह आशय ज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है. अमेरिका की वाणिज्य सचिव सुश्री पेन्नी प्रिटजकर ने इस ज्ञापन को नई दिल्ली में 31 जुलाई, 2014 को होने वाली यूएस-इंडिया के बीच रणनीतिक बातचीत की पूर्व पीठिका के रूप में माना. यह ज्ञापन दोनों देशों के बीच बढ़ते वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह ज्ञापन दोनों देशों के बीच मजबूत वाणिज्यिक संबंधों पर जोर देता है. ज्ञापन की शर्तों के अंतर्गत दोनों पक्ष द्विपक्षीय निवेश प्रवाहों तथा निवेश अवसरों पर जानकारी चाहने वाले विद्यमान तथा संभावित निवेशकों के लिए एक मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे. दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त राज्य में मौजूदा तथा भावी निवेशकों के लिए भारत तथा अमेरिका में संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने अमेरिका में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर, 2014 को सेलेक्ट यूएसए के साथ एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया. सेलेक्ट यूएसए के कार्यपालक निदेशक तथा राजदूत श्री विनय थुमालापल्ली के नेतृत्व में सेलेक्ट यूएसए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तथा अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली से गणमान्य व्यक्तियों सहित अमेरिकी महा वाणिज्यदूत, मुंबई इस कार्यक्रम में उपस्थित थे.

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए जेबिक (जेबीआईसी) के साथ साझेदारी

एक्ज़िम बैंक ने भारत तथा इसके सहयोगी देशों के बीच कनेक्टिविटी तथा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहयोग की संभाव्यता का संयुक्त रूप से तलाश करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आर्थिक सहयोग तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थाएं अन्य देशों (जैसे अफ्रीकी देशों जहां भारतीय तथा जापानी कंपनियां मौजूद हैं) में वित्तपोषण व्यवसाय अवसरों का पता लगाएंगी.

भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी तथा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष जनवरी माह में भारत सरकार तथा जापान सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में सहयोग की घोषणा की गई है जिससे सीमापार कारोबार में सुधार होगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में आर्थिक वृद्धि तथा विकास को गति मिलेगी.

विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष बाह्य निवेश (ओडीआई) में गिरावट

भारत से प्रत्यक्ष बाह्य निवेश (ओडीआई) की मात्रा में वृद्धि के साथ- साथ इसके भौगोलिक विस्तार तथा क्षेत्रगत संरचना में भी काफी परिवर्तन हुआ है. एक्ज़िम बैंक का हालिया शोध अध्ययन ''भारत से प्रत्यक्ष बाह्य निवेश: रुझान, उद्देश्य व नीतिगत परिदृश्य'' यह दर्शाता है कि भारत का ओडीआई 2001-02 के 1.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2011-12 में 30.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है. तथापि अध्ययन में यह बात भी सामने आयी है कि क्षेत्रगत वितरण की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो पिछले कई दशकों से ओ डी आई के लिए पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है. हालांकि इसका महत्व अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. इस प्रकार जहां भारत के ओडीआई में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2003-04 में 59.8% था वहीं 2011-12 में इसका हिस्सा घटकर 31.5 प्रतिशत रह गया है. विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद वर्ग (संचयी निवेश की दृष्टि से) सबसे बड़ा वर्ग रहा जिसके बाद फार्मास्युटिकल, औषधि रसायन, वनस्पतिक उत्पाद तथा मोटर वाहन रहे. हालांकि इसी अवधि के दौरान क्षेत्रीय संवितरण जहां स्थिर रहे वहीं दशक के उत्तरार्द्ध में फैब्रीकेटेड मेटल उत्पाद (मशीनरी और उपकरण को छोड़कर) तथा विशिष्ट प्रयोजन मशीनरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया.

भारत के परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक्ज़िम बैंक ने भारत के परियोजना निर्यात में तीव्र उछाल के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए 'परियोजना निर्यात पर अंशधारक सेमिनार' का आयोजन किया. ऋण-व्यवस्था तथा क्रेत-ऋण जैसे बैंक के कार्यक्रम भारतीय परियोजना निर्यातकों को विकासशील देशों के नए बाजारों में प्रवेश करने तथा भारत से माल एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने में समर्थ बनाते हैं. एक्ज़िम बैंक अफ्रीकी विकास बैंक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी (पीडीसी) की भी स्थापना कर रहा है जो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर फोकस करेगी जो भारत के लिए विशिष्ट रणनीतिक महत्व रखती हों. पीडीसी चिन्हित परियोजनाओं को परियोजना विकास विशेषज्ञता सुविधाएं प्रदान करेगी.

ऊर्जा पर्याप्तता हासिल करने और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है. सतत विकास की दिशा में अपने प्रयासों में भारत के वैश्विक रूप से अधिक उत्तरदायी होने के नाते देश की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होगी.

मुख्यतः ऊर्जा सुरक्षा, सरकारी प्रोत्साहन और जलवायु परिवर्तन के कारण की गई पहलों के चलते भारत में स्वच्छ ऊर्जा तथा नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन में निवेश बढ़ रहा है. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2002-03 में 3.9 जीडब्ल्यू से बढ़कर मार्च 2014 में लगभग 31.7 जीडब्ल्यू हो गयी है. 31 जुलाई, 2014 को बिजली क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 12.9 प्रतिशत रहा (**चार्ट**).

भारत में पवन ऊर्जा

विस्तृत प्रायद्वीपीय पट्टी और दो-मौसमी मानसून के चलते भारत के पास पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की विपुल संभाव्यता है. तटीय क्षेत्र के अलावा भारत के पास पवन ऊर्जा के लिए अपतटीय पट्टियों का भी उपयोग करने की संभाव्यता है. यहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों के लिए पवन ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हैं. भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है. पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता वृद्धि मुख्यतः उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) द्वारा उत्प्रेरित है जहां उत्पादक को 10 मिलियन रुपये प्रति मेगावॉट की अधिकतम सीमा के अधीन उत्पादन की गई बिजली के प्रति यूनिट पर 50 पैसे मिलते हैं. जीबीआई ईक्विटी आंतरिक प्रतिफल दर में 140-150 आधार बिन्दु का सुधार लाती है, इस प्रकार उन राज्यों में इसका आकर्षण बढ़ जाता है जहां अधिमान्य टैरिफ 4.9 रुपये प्रति यूनिट से कम है.

त्वरित मूल्यह्रास लाभ, जो 2011-12 में समाप्त हो गया, पहले वर्ष में पवन ऊर्जा आस्तियों पर 80 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति देता है.

महाराष्ट्र, राजस्थान तथा आंध्रप्रदेश द्वारा आकर्षक अधिमान्य टैरिफ के चलते पवन ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है.

भारत में सौर ऊर्जा

ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से नवीकरणीय ऊर्जा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत सौर उर्जा है जो यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. भारत को प्रति वर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन केडब्ल्यूएच के समतुल्य सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जो भारत की ऊर्जा खपत से अधिक है. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) देश में सौर ऊर्जा के विकास का एक महत्वपूर्ण संस्थान है. तमाम प्रोत्साहनों के बावजूद भारत में इसकी संभाव्यता के सिर्फ एक हिस्से का ही उपयोग हुआ है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा लागू की गई नीतियों के चलते वर्ष 2013-14 में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 990 मेगावॉट की क्षमता वृद्धि देखी गई. पवन ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समाप्त हो जाने से सौर ऊर्जा की ओर विशेष झुकाव की उम्मीद है.

जेएनएनएसएम चरण II नीति के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 2014 के दौरान निर्मित की जाएंगी और राज्य परियोजनाओं के भी एक वर्ष में शुरू हो जाने की उम्मीद है. जेएनएनएसएम के चरण II में अब यह स्पष्ट किया गया है कि परियोजनाओं का 50 प्रतिशत (375 मेगावॉट) देशी रूप में विनिर्मित सेलों तथा मॉड्यूलों से निर्मित किया जाना चाहिए. इसी प्रकार, राज्यों की वर्तमान तथा भावी राज्य नीतियों में देशी वस्तुओं के प्रयोग की अपेक्षा जैसे प्रावधान स्थानीय विनिर्माताओं को जबर्दस्त बढ़ावा देंगे तथा दीर्घावधि में सौर ऊर्जा व्यवसाय को लाभप्रद बनाएंगे.

भारत में बायोमास ऊर्जा

बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कृषि अवशिष्टों जैसे खोई, धान की भूंसी, पुआल, कपास के डंठल, समुद्री घास, नारियल की खोपड़ी तथा जंगल के ऑर्गेनिक अवशिष्टों जैसे लकड़ी, पौधे आदि का उपयोग किया जाता है. भारत में बायोमास की उपलब्धता कृषि, वानिकी तथा बागान से अवशिष्टों को शामिल करते हुए 160 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक अनुमानित है. लगभग 70-75 प्रतिशत अवशिष्टों का उपयोग चारे, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में तथा अन्य आर्थिक प्रयोजनों के लिए होता है. एमएनआरई अनुमानों के अनुसार, शेष 25-30 प्रतिशत उपयोज्य औद्योगिक तथा कृषि अवशिष्ट प्रति वर्ष बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध है. यह संभाव्य बिजली उत्पादन क्षमता 17,500 मेगावॉट से अधिक में रूपांतरित होती है. देश में मौजूदा चीनी मिलों के आधार पर खोई आधारित सह-उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त 5000 मेगावॉट की क्षमता जोड़ी जा सकती है.

भावी संभावनाएं

यद्यपि इस क्षेत्र में काफी संभाव्यता है और उद्योग के लिए काफी सरकारी प्रोत्साहन भी विद्यमान हैं किन्तु अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है. नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) को सख्ती से लागू करने की इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए. भविष्य में, बढ़ती प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और देश में ऊर्जा तक विस्तृत पहुंच से नवीकरणीय ऊर्जा खंड में बिजली की क्षमता में वृद्धि होने की आशा है.

चार्ट :बिजली क्षेत्र में ईंधन-वार संस्थापित क्षमता (31जुलाई,2014 को)

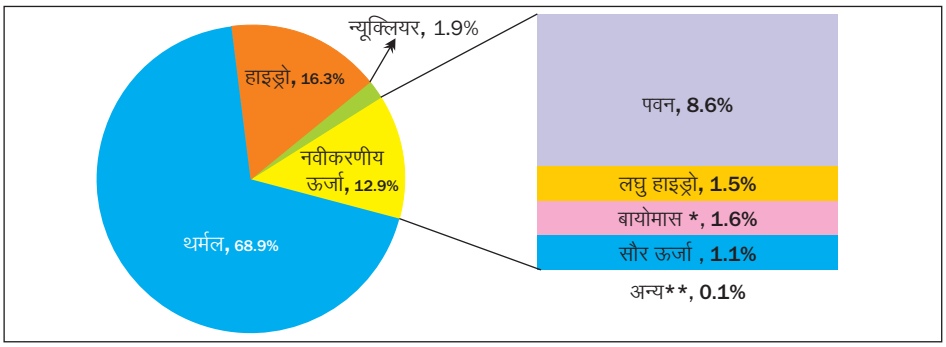

* खोई सह-उत्पादन शामिल है ** अवशिष्ट से बिजली शामिल है

स्रोत : बिजली मंत्रालय, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध के लिए वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार प्रदान कर रहा है. इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है. इस पुरस्कार की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू , की जन्म शताब्दी (1889-1989) के उपलक्ष्य में की गई है.

पुरस्कार के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में डॉक्टरेट की दिशा में शोध कार्य करने वाले आवेदकों से प्रविष्टियां आमंत्रित कर स्वतंत्र जूरी द्वारा पुरस्कार विजेता प्रविष्टि का चयन किया जाता है. पुरस्कार के विवरण भारत तथा विदेशों में समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नलों में विज्ञापन तथा इंटरनेट के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं. पुरस्कार के रूप में दो लाख पचास हजार रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है.

पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां

भारत या विदेश में किसी विश्वविद्यालय या समतुल्य शैक्षिक संस्था से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों द्वारा शोध कार्य (या तो डॉक्टरेट उपाधि प्रदत्त या डॉक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकृत) पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है. प्रस्तुतीकरण की मौलिकता तथा स्पष्टता को वरीयता दी जाती है. भारत / एक्ज़िम बैंक से संबंधित विषयों जैसे विदेश व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, व्यापार एवं निवेश को प्रभावित करने वाली नीतियां, मौद्रिक तथा राजकोषीय हस्तक्षेप आदि को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है. पुरस्कार भारतीय रुपये में पात्र व्यक्तियों को दिये जाएंगे. पुरस्कार के लिए एक्ज़िम बैंक ऐसी प्रविष्टियों को ही स्वीकार करता है जिन पर पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष के पूर्ववर्ती चार कैलेंडर वर्षों के दौरान या पुरस्कार दिये जाने वाले चालू वर्ष के 30 सितंबर तक डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई है या डॉक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकार किया गया है. शोध अंग्रेजी या हिंदी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और हिंदी के मामले में उसका अंग्रेजी अनुवाद दिया जाना चाहिए. पिछले 25 वर्षों (1989-2013) के दौरान बैंक द्वारा 33 शोध-प्रबंधों को ईरा पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसमें से चुने गये 13 शोध प्रबंध विदेशी विश्वविद्यालयों में किए गए थे.

पुरस्कार की स्थापना के समय से ही उच्च गुणवत्तापूर्ण शोधों को ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पुरस्कार विजेता शोधों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिमय दर व्यवस्था, विकासशील देशों के विदेशी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम, विदेश व्यापार व्यवस्था तथा रणनीतिक व्यापार नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शोध शामिल है. पुरस्कार विजेता डॉक्टोरल शोधों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं. प्रमुख पुरस्कार विजेता हैं : डॉ. नागेश कुमार, डॉ. तरुण कविराज, डॉ. ए प्रसाद, डॉ. रजत आचार्य, डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, डॉ अवधूत नाडकर्णी, डॉ. पूनम गुप्ता, डॉ सजिद चिनॉय, डॉ प्रवीण कुमार, डॉ. देव कुसुम दास, डॉ. रश्मि बंगा, डॉ प्राची मिश्रा तथा डॉ. देबाशीष मंडल. इस पुरस्कार को मिलने वाला आदर व सम्मान का इस बात से पता चलता है कि पुरस्कार के पिछले कुछ विजेताओं में आज के प्रमुख अर्थशास्त्री, शोध विद्वान तथा शिक्षाविद् शामिल हैं.

2013 के लिए ईरा पुरस्कार का परिणाम

30 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री यदुवेन्द्र माथुर द्वारा 2013 के एक्ज़िम बैंक ईरा पुरस्कार घोषणा की गई. पुरस्कार ज्यूरी ने प्रविष्टियों के मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2013 के लिए ईरा पुरस्कार के विजेता के रूप में डॉ. अन्वेषा आदित्य के चयन की सिफारिश की. इस पुरस्कार की सिफारिश उनके शोध प्रबंध `ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्रोडक्ट वेरायटी एंड ग्रोथ' पर की गई है. डॉ. आदित्य ने जाधवपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 2013 में अपनी डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है. यह शोध प्रबंध डॉ. रजत आचार्य के पर्यवेक्षण में लिखा गया है. वे वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर हैं. अपने शोध प्रबंध में डॉ आदित्य ने अनुभवजन्य तथा सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए आर्थिक वृद्धि पर व्यापार उदारीकरण, उत्पाद विविधता तथा निर्यात संरचना के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है. अध्ययन में यह भी विवेचना की गई है कि व्यापार वृद्धि संबंध बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं तथा राष्ट्र विशिष्ट संस्थानों, देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उत्पादकता सीमाओं जैसे मानव पूंजी तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) आदि पर कितना निर्भर रह सकता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की सदस्य तथा तेरहवें वित्त आयोग की सदस्य डॉ. इंदिरा राजारामन द्वारा डॉ अन्वेषा आदित्य को पुरस्कार प्रदान किया गया. उन्होंने इस अवसर पर डॉ. आदित्य के पुरस्कार विजेता शोध प्रबंध पर एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख `ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्रोडक्ट वेरायटी एंड ग्रोथ' का विमोचन भी किया .

विपणन सलाहकारी सेवाएं
जुलाई - सितंबर, 2014

एक्जिम बैंक ने कन्सर्न इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर आर्ट फॉर कन्सर्न प्रदर्शनी में गोंड पेंटिंग्स प्रदर्शित करने के लिए मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्पकारों को सहायता प्रदान की. सिक्युर गिविंग एंड कनसर्न इंडिया फाउंडेशन द्वारा 23-25 सितंबर, 2014 के दौरान मुंबई को आयोजित पारम्परिक तथा लोक कला प्रदर्शनी में एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई. कार्यक्रम के आयोजन में सहायता का उद्देश्य नए बाजार अवसरों का पता लगाने में सहायता प्रदान करना और बड़ी संख्या में संभावित क्रेताओं तक पहुंचना था.

गोंड पेंटिंग्स मध्य प्रदेश के गोंड ट्राइब के परधा उप-समूह द्वारा बनाई जाती हैं. ये पेंटिंग्स पेड़ पर या पेड़ के नीचे जीवन की सुंदर प्रस्तुति करती हैं. इन पेंटिंगों में किनारे नहीं होते हैं और यह बिन्दुओं के विस्तार पर आधारित होती हैं. गोंड चित्रकार एक बिंदी से पेंटिंग शुरू करते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार पूर्ण तस्वीर उभारने के लिए ऊपर, नीचे, बगल में कई बिंदियां लगाते हैं. ये बिंदियां प्रायः बीच-बीच में रोकी जाती हैं और दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार तथा त्रिभुजाकार आकारों द्वारा भरी जाती हैं. गोंड पेंटिंग्स की थीम लोक कलाओं, आदिवासी कथाओं, कहानियों तथा मिथकों पर आधारित होती है.

इस प्रदर्शनी में पूरे भारत से कलात्मक हेरिटेज तथा कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं जिनमें चोला ब्रांज मूर्तिकला, फड़, गोंड एवं मधुबनी पेंटिंग्स, सूती कपड़ों पर कलमकारी तथा कालीघाट पेंटिंग, माता नी पचेड़ी पेंटिंग, मिनिएचर आर्ट, पिचवई फैब्रिक पेंटिंग और टेराकोटा कला शामिल है. तीन दिन की इस प्रदर्शनी के दौरान कुल 27 पेंटिंग्स बिकीं और प्रदर्शनी में 200 से अधिक अतिथि पधारे.

एक्ज़िम बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता सृजन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक भूमिका अदा करता है. एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातक फर्मों के उत्पादों एवं सेवाओं के लिए विदेशी वितरकों /क्रेताओं / साझेदारों की पहचान करने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करते हुए उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता करने का प्रयास करता है.

इस अनोखे कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा, हस्तशिल्प तथा हैंडलूम से लेकर कृषि तथा खाद्य एवं पेय, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल एवं सौंदर्य प्रसाधन, पुष्पकृषि तक विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बैंक द्वारा मार्केटिंग की गई.

बैंक विदेशों में अपने कार्यालयों, अपनी उच्च स्तरीय साख, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गहन जानकारी और सुस्थापित संस्थागत सहबद्धताओं का लाभ लेकर सफलता शुल्क आधार पर भारतीय कंपनियों के उत्पादों की विदशों में मार्केटिंग में सहायता करता है.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई

फोन नं. : (022) 22172829

ई-मेल : mas@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

'द जी-20 मैक्रोइकोनॉमिक एजेंडा : इंडिया एंड इमर्जिंग इकोनॉमिज'

जी-20 का गठन एशियाई वित्तीय संकट के दौरान दिसंबर 1999 में किया गया था. वैश्विक आर्थिक अभिशासन के प्रमुख फोरम के रूप में जी-20 वर्ष 2008-09 के वैश्विक आर्थिक संकट का निवारण करने तथा उसे पूर्ण विकसित मंदी का रूप धारण करने से रोकने में सफल रहा. जी-20 ने अपनी स्थापना पर वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की और मैको आर्थिक प्रबंधन के लिए जी-7 तथा नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर अप्रत्याशित वैश्विक सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा. वर्ष 2010 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार आने पर जी-20 ने अपने कार्यों में विशेषकर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, पण्यों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक बचतों का पुनः निवेश करने और ऊर्जा तथा पर्यावरण संपोषणीयता को बढ़ाने संबंधी एक नया विकास एजेंडा शामिल किया.

पुस्तक में जी-20 की सफलता में भारत की भूमिका सहित जी-20 तथा अन्य वैश्विक व्यवस्थाओं में भारत की सक्रिय सहभागिता तथा संभावित बाधाओं का भी वर्णन किया गया है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था यूरो संकट तथा संयुक्त राज्य में धीमे आर्थिक कार्य-निष्पादन तथा प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से ग्रसित है. इस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक शोध प्रबंधों की दृष्टि से पुस्तक संग्रहणीय है. पुस्तक जी-20 के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सहित वित्तीय तथा आर्थिक दृष्टि से अनसुलझे मुद्दों और भावी कार्य-योजना को रेखांकित करती है.

अंगोला

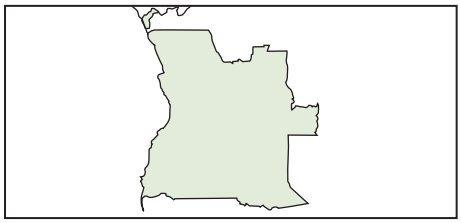

अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने 2013 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 7.1 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है. तेल क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मूलाधार है. अतः इसका विविधीकरण करने और तेल क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है. अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने और बेरोजगारी का मुकाबला करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास योजना में सार्वजनिक निवेश किए गए हैं. जुलाई 2013 से तेल कंपनियों को अपने लेन-देन स्थानीय मुद्रा में करने के लिए बाध्यकारी नियम कीमतों में उछाल को बढ़ावा दे रहे हैं. 2009 से पहली बार 2013 में दर्ज किए गए राजकोषीय घाटे के 2014 में गहरा जाने की संभावना है. अंगोलियाई बैंकिंग क्षेत्र, तेल क्षेत्र पर भारी निर्भरता और मुश्किल के दौर में विदेशी (विशेषकर पूर्तगाली) बैंकिंग प्रणाली में इसके एक्सपोजर से कमजोर हुआ है. इसके अलावा, तेल कंपनियों द्वारा अपने लेन-देन स्थानीय बैंकों के माध्यम से करने संबंधी हालिया नियम से परिणामी नकदी प्रवाह का प्रबंध करने में बैंकिंग प्रणाली की क्षमता प्रश्नों के घेरे में है.

मोजाम्बिक

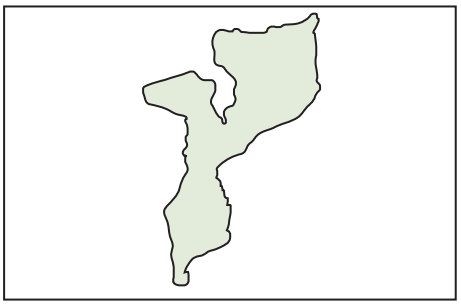

2013 में वास्तविक जीडीपी में 7 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि यह वृद्धि वर्ष के प्रारंभ में भयंकर बाढ़ के कारण उम्मीद से कम रही. निष्कर्षण क्षेत्र पर संकेन्द्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वृद्धि के मुख्य संवाहक रहे हैं. कोयले के उत्पादन में प्रगामी वृद्धि और बजट में विस्तार के साथ विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 2014 में 7.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है. समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी नीति का कार्यान्वयन जारी रहने की उम्मीद है.

उज़बेकिस्तान

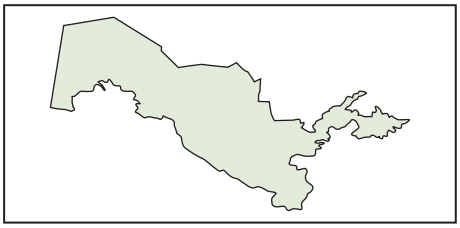

उज़बेकिस्तान में आर्थिक कार्यकलाप मुख्यतः गैस निर्यात क्षेत्र से उत्पन्न राजस्व द्वारा संचालित हैं. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिकीकरण में भारी निवेश करना जारी रखा है. वर्तमान में उज़बेक अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं 2011-15 के लिए "औद्योगिक आधुनिकीकरण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम और पुनर्निर्माण एवं विकास निधि" के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं. ऐसी संभावना है कि उज़बेकिस्तान की दीर्घावधिक वृद्धि संभावनाएं विशेषकर संरचनात्मक सुधारों को कार्यान्वित करने में धीमी प्रगति, सरकार द्वारा लगातार निर्देशित उधार प्रणाली, सीमित मुद्रा परिवर्तनीयता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से मुक्ति द्वारा बाधित होंगी. उज़बेकिस्तान की व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन पर आधारित है. 2013 में सरकार ने कई उपभोक्ता वस्तुओं पर अतिरिक्त प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण लगाने का एक नया उपाय शुरू किया जिससे आयात नियंत्रित हुआ. तथापि उद्योग क्षेत्र (गैस को छोड़कर) की कमजोरी को देखते हुए अर्थव्यवस्था के कई हिस्से आयात पर निर्भर हैं.

पनामा

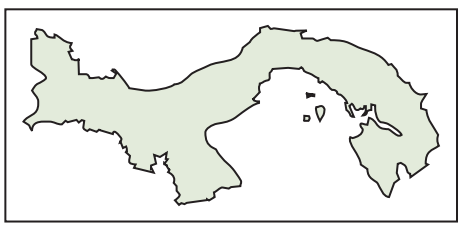

विश्व आर्थिक फोरम की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार, पनामा मध्य अमेरिका में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी देश है. पनामा की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं की बदौलत 2013 में 6.5 प्रतिशत बढ़ी. देश के जीडीपी में निवेशों का एक-तिहाई हिस्सा है, जबकि शेष लैक क्षेत्र में इसका 25 प्रतिशत हिस्सा है. पनामा के डैरिन जंगल में तेल भंडार की हालिया खोज, जो 900 मिलियन बैरल तक हो सकता है, ने देश के लिए आयातित तेल तथा उससे संबंधित ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग खोल दिया है.

वियतनाम

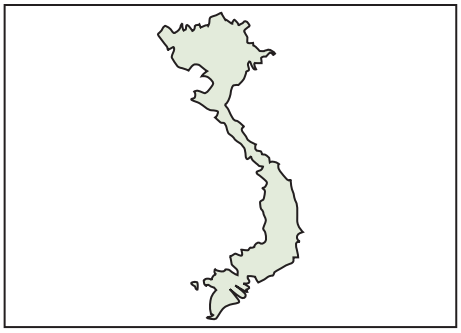

1997 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान मामूली गिरावट के बाद वियतनाम की वृद्धि दर 2000-2007 के दौरान औसतन 7.5 प्रतिशत रही. जोरदार देशी वृद्धि तथा जनवरी 2007 से डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद उच्चतर निवेश की बदौलत 2007 में जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई. तथापि वैश्विक मंदी ने 2008 में इस निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था को मंद कर दिया. 2013 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही. देशी ऋण की आसान उपलब्धता के कारण हाल के वर्षों में वियतनाम में मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही है तथापि 2013 में मुद्रास्फीति की दर 2012 के 18.7 प्रतिशत की उच्च दर की तुलना में घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, शिक्षा तथा परिवहन ने उन क्षेत्रों की तुलना में उच्चतर तथा अधिक अस्थिर मुद्रास्फीति दर्ज की है जहां कीमतें मुख्यतः बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं. अन्य क्षेत्रीय समकक्षियों में वियतनाम में मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही. वर्ष 2013 में, वियतनाम ने न्यून मुद्रास्फीति, जोरदार बाह्य व्यापार तथा पूंजी प्रवाह और स्थिर विनिमय दर के साथ आर्थिक स्थिरता के तीसरे वर्ष में प्रवेश किया है.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वर्तमान में विश्व विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की छठीं सबसे अधिक क्रय-विक्रय की जाने वाली मुद्रा है जिसका विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा लेन-देन में 6 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. चूंकि ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में पण्यों का भारी अनुपात होता है, अतः पण्य मूल्यों तथा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बीच घनिष्ठ संबंध हैं. जब पण्यों की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य बढ़ता है और जब वैश्विक कीमतें घटती हैं तब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य घटता है. फलस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को कभी-कभी `पण्य मुद्रा' भी कहा जाता है.

लगातार तीन वर्षों तक मजबूती के बाद यूएस डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के कमजोर होने का अनुमान है. 2014-15 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्यह्रास होगा और यह 2015 के मध्य तक निम्न स्तर पर पहुंच सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर सकारात्मक मुद्रास्फीति के चलते पौंड, यूरो तथा यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ. जिससे रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ब्याज दर स्थिरता का लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिली है. ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में उपभोक्ता मूल्य वर्ष की तीसरी तिमाही में अपेक्षित स्तर से अधिक बढ़ा. उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 0.5 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है. वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर बाजार अपेक्षाओं के अनुरूप अंतिम तिमाही में 2.3 प्रतिशत बढ़ी.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को एक मात्र जोखिम अमेरिकी आंकड़ों से है जो इसे अन्य प्रमुख समकक्षी देशों के मुकाबले पीछे कर सकता है.

30 सितंबर, 2014 को 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर= 0.8732 यूएस डॉलर पर उद्धृत हो रहा था.

दक्षिण अफ्रीकी रैंड

दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है क्योंकि चालू खाते का घाटा दूसरी तिमाही में बढ़कर जीडीपी का (-) 6.2 प्रतिशत हो गया है. निर्यात तथा पण्य कीमतों में निरंतर कमजोरी बाह्य घाटे पर और दबाव का संकेत देती है. मुद्रास्फीति की दर हालांकि ऊंची बनी हुई है, किंतु पण्य कीमतों के साथ घटनी चाहिए. अधिकांश उभरते बाजारों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के अधोमुखी जोखिमों तथा स्थिर दरों को देखते हुए ऐसी आशा की जाती है कि उभरते बाजारों की ओर से कोई भी कड़ाई चक्र मुश्किल भरा होगा.

व्यापक मुद्रा प्रवाह के संयुक्त राज्य की ओर बढ़ने पर उच्च आय वाली मुद्राएं जैसे ऑस्ट्रेलियाई तथा न्यूजीलैंड डॉलर तथा दक्षिणी अफ्रीकी रैंड (ज़ार) भी दबाव में आएंगी. यूएस फेडरल रिज़र्व अमेरिकी परिसंपत्तियों पर आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए 2015 में ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया में है.

यूएस में निम्न दरों की इस अवधि के दौरान तथाकथित पण्य मुद्राओं जैसे ज़ार को लाभ हुआ है. निवेशक निम्न दरों पर आसानी से उधार ले सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्थानों में उच्चतर आय का लाभ उठा सकते हैं. यूनाइटेड किंगडम के मामले में भी यही बात लागू होती है. रेकॉर्ड न्यून दरों में शीघ्र ही बदलाव होगा और इससे यूके तथा यूएस को दक्षिण अफ्रीका से प्रवाह बढ़ेगा.

मूल्यह्रास की क्रमिक प्रवृत्तियों के पुनः शुरू होने से पूर्व रैंड के 2015 में औसतन मजबूत होने का पूर्वानुमान है. व्यापक रूप से क्रय-विक्रय की जाने वाली मुद्रा होने के नाते रैंड पूर्वानुमान अवधि (2014-18) के दौरान अस्थिर रहेगा. इसके अलावा, विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो निवेश की अस्थिरता मुद्रा की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेगी. 30 सितंबर, 2014 को ज़ार 1 यूएस डॉलर =11.30 ज़ार पर उद्धृत हो रहा था.

चीनी युआन

चीन ने वर्ष 1979 से एक दोहरी विदेशी मुद्रा विनिमय दर अपनायी है. 1994 में इसने धीमी गति से परिवर्तित होने वाली युआन दर सृजित करने के लिए दरों को एकीकृत किया. यह दर युआन को एशियाई वित्तीय संकट तक 8.28 प्रति यूएस डॉलर से 8.30 प्रति यूएस डॉलर की दर पर केन्द्रित दायरे में घटने-बढ़ने की अनुमति देती है और उसके बाद यह 8.28 प्रति यूएस डॉलर पर वस्तुतः स्थिर रही है. चीन ने स्थिर दर व्यवस्था से अस्थिर दर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 21 जुलाई, 2005 को अपनी मुद्रा का 2.10 प्रतिशत अवमूल्यन करते हुए 8.11 प्रति यूएस डॉलर की दर से पुनर्मूल्यन किया. इस व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक (पीपल्स बैंक ऑफ चाइना) हरेक दिन युआन को पिछले दिन की बंद दर पर केन्द्रीय बैंक के मध्य दर पर पुनर्निर्धारण से 0.30 प्रतिशत (जो मई 2007 में बढ़कर 0.50 प्रतिशत हो गई) तक बढ़ने तथा घटने की अनुमति देता है.

युआन पिछले छः महीने से अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के मुकाबले मजबूत हो रहा है , लेकिन चीन के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के मुकाबले तेजी समाप्त हो सकती है, क्योंकि उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक `लघु अवमूल्यन' किए जाने की संभावना है.

पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने युआन की मूल्यवृद्धि पर एकतरफा नियंत्रण लगाने के लिए पहली तिमाही में युआन को 2.6 प्रतिशत (जो 1994 से सर्वाधिक है) कमजोर करने के लिए डॉलर की खरीदी की. चीनी मुद्रा दूसरी तिमाही में 0.2 प्रतिशत बढ़ी और 30 जून से 1.4 प्रतिशत मजबूत हुई, ब्लूमबर्ग द्वारा ट्रैक की गई 31 प्रमुख विनिमय दरों में यह एकमात्र मुद्रा थी जो फायदे में रही.

वर्ष 2015 में यूएस डॉलर के मुकाबले युआन में धीमे-धीमे मजबूती बनी रहने की उम्मीद है. 30 सितंबर, 2014 को चीनी युआन 1 यूएस डॉलर = 6.1382 युआन पर उद्धृत हो रहा था.

एक्ज़िम बैंक की ग्रामीण पहल के अंतर्गत ग्रामीण हस्तशिल्प की गतिशीलता को समझने के लिए शिवगंगा, तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यशाला की परिणिति 2011 में एक्ज़िम में ग्रासरूट पहल तथा विकास (ग्रिड) की स्थापना के रूप में हुई. ग्रिड समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित उद्यमों के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करता है. यह पहल बैंक के अन्य सहायता कार्यक्रमों की अनुपूरक है और देश के पारम्परिक शिल्पियों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करते हुए समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है. इसका उद्देश्य बैंक के व्यापक संस्थागत ढांचे का भरपूर उपयोग करते हुए नए भौगोलिक क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समर्थकारी वातावरण सृजित करना है.

बैंक विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ करने, उन्हें विकसित करने तथा उनका संपोषण करने का निरंतर प्रयास करता रहा है. बैंक ने क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुंच, प्रशिक्षण में सहायता आदि के द्वारा रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन में योगदान देकर शिल्पकारों तथा अन्य लक्ष्य खंडों तक सीधे पहुंचने के उद्देश्य से चुनिंदा व्यापार संगठनों के साथ औपचारिक सहयोग करार किए हैं.

इस पहल के माध्यम से बैंक ग्रासरूट पहलों / प्रौद्योगिकियों, विशेषकर निर्यात संभाव्यता वाली पहलों / प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देश भर में शिल्पकारों , उत्पादक समूहों, क्लस्टरों, लघु उद्यमों, एनजीओ की अपने उत्पादों पर लाभप्रद प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करता है और अंत में इन इकाइयों से निर्यात सुगम बनाता है. यह समूह एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) के रूप में कार्य करता है और ग्रामीण /ग्रासरूट स्तर पर कार्यरत संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

ग्रासरूट पहलों के अंतर्गत योजनाओं को इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वे ग्रासरूट संगठनों द्वारा महसूस की जाने वाली तीन प्रमुख अड़चनों प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वित्त तक पहुंच, कौशल विकास तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार की तलाश का समाधान करें अर्थात्. निधियों की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य यह समूह कारोबार को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. क्षमता तथा कौशल विकास के लिए समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाइन विकास कार्यशाला, उत्पादों के लिए पैकेजिंग समाधान और गुणवत्ता सुधार सेमिनार आयोजित करने में सहायता करता है.

समूह को एक संतुलित तथा संपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कार्य करने का अधिदेश (मैंडेट) दिया गया है. समूह उत्पाद विकास / कारोबार चक्र के प्रत्येक चरण मे (अर्थात क्षमता निर्माण, निर्यात क्षमता सृजन तथा विस्तार में सहायता प्रदान कर विविधीकरण और अंत में निर्यात), उन मुद्दों का समाधान करने में उद्यमों की सहायता करता है जो निर्यात करने से उन्हें रोकते हैं. बैंक द्वारा (ग्रिड) समूह के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता में क्षमता निर्माण, सामान्य सुविधा केन्द्र विकसित करना, कच्चा माल बैंक विकसित करना, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा एमएसएमई, ग्रासरूट ग्रामीण उद्यमों आदि में निर्यात क्षमता सृजित करना आदि शामिल हैं.

समूह विभिन्न ग्रासरूट संगठनों /उद्यमों जैसे शिल्पकार, बुनकर सहकारी समितियों, सोसायटियों, एनजीओ, ट्रस्टों, आजीविका सृजन की दिशा में कार्यरत क्लस्टरों आदि को सहायता प्रदान करता है.

लगभग तीन साल पहले ही शुरु किए गए इस समूह के कार्यकलाप क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं. अपनी विकास यात्रा में समूह ने प्रौद्योगिकी उन्मुख और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की उच्च संभाव्यता वाले अपेक्षाकृत नये उद्यमों को भी शामिल किया है. उदाहरण के लिए बैंक ने आईआईटी, चेन्नै के रूरल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर (आरटीबीआई) के कारोबारी इंक्यूबेटीज को सहायता प्रदान करने के लिए आरटीबीआई के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

भारत से हैंडलूम तथा हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन तथा विपणन (मार्केटिंग) में ग्रामीण उद्यमों की सहायता करने के लिए भारत हैंडलूम मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (बीएचएमसीएल) की स्थापना समूह द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है. यह कंपनी एक्ज़िम बैंक, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एनएचडीसी) तथा एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड अपेक्स सोसायटीज ऑफ हैंडलूम्स (एसीएएसएच) की ईक्विटी सहभागिता से युक्त एक संयुक्त उद्यम कंपनी है. बीएचएमसीएल बाजार सर्वेक्षण तथा अनुसंधान सहित हैंडलूम उत्पादों के बारे में जानकारी एकत्र करेगी तथा बुनकरों एवं शिल्पकारों के लिए डाटा बैंक के रूप में कार्य करेगी. यह भारत से हैंडलूम उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लिंकेजेज स्थापित करने में सहायता करेगी तथा भारत में हैंडलूम सेक्टर के लिए कल्याण / विकास योजनाएं शुरू करेगा.

इस प्रकार, ग्रासरूट संगठनों से निर्यात को बढ़ावा देने के बैंक के उद्देश्य को बीएचएमसीएल द्वारा उत्पाद विकास तथा बाजार पहुंच पर फोकस से सहायता मिलेगा.

संक्षेप में, ग्रिड का लक्ष्य एक संपूर्ण दृष्टिकोण (क्षमता निर्माण, निर्यात क्षमता सृजन विस्तार , विविधीकरण तथा अंत में निर्यात बढ़ाने में सहायता) विकसित करते हुए निर्यात बाधाओं का समाधान कर ग्रास रुट उद्यमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने में समर्थ बनाना है.

संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1224.1	1365.4	1708.5	1880.3	1858.7	1877.5[e]	2134.7[f]
जीडीपी प्रति व्यक्ति (यूएस डॉलर)	1044.9	1146.7	1411.7	1528.7	1486.8	1472.1[e]	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि(%)*	6.7	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7[e]	5.7[e] (अप्रैल-जून)
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.1	0.8	8.6	5	1.4	4.7[e]	3.8[e] (अप्रैल-जून)
उद्योग	4.4	9.2	7.6	7.8	1	0.4[e]	4.2[e] (अप्रैल-जून)
सेवाएं	10	10.5	9.7	6.6	7	6.8[e]	6.8[e] (अप्रैल-जून)
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)							
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	15.8	14.6	14.6	14.4	13.9[e]	14.0[p]	13.4[e] (अप्रैल-जून)
उद्योग	28.1	28.3	27.9	28.2	27.3[e]	26.1[p]	26.2[e] (अप्रैल-जून)
सेवाएं	56.1	57.1	57.5	57.4	58.8[e]	59.9[p]	60.4[e] (अप्रैल-जून)
जनसंख्या (मिलियन)	1171.5	1190.7	1210.2	1230	1250.2	1270.6[e]	-
मुद्रास्फीति की दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.1	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0	2.38 (सितंबर'14)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	6.0	6.5	4.8	5.7	4.8	4.6	4.1[e]
विनिमय दर (₹ / यूएस डॉलर, औसत)	45.9	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	61.61 (सितंबर30,'14)
विनिमय दर (₹ / यूरो, औसत)	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	7	8.21 (सितंबर 30,'14)
निर्यात(बिलियन यूएस डॉलर)	185.3	178.8	251.1	306	300.4	314.4	161.5 (अप्रैल-सितंबर)
% परिवर्तन	13.6	-3.5	40.5	21.8	-1.8	4.7	5.0^
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	27.5	28.2	41.5	56	60.9	63.2	33.7 (अप्रैल- सितंबर)
% परिवर्तन	-3	2.3	47.2	34.9	8.7	3.8	3.0^
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	157.7	150.6	209.6	250	239.5	251.2	127.8 (अप्रैल- सितंबर)
% परिवर्तन	17.1	-4.6	39.2	19.3	-4.2	4.9	5.6^
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	303.7	288.4	369.8	489.3	490.7	450.2	234.2 (अप्रैल- सितंबर)
% परिवर्तन	20.7	-5.1	28.2	32.3	0.3	-8.3	1.6^
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	93.7	87.1	106	155	164	164.8	82.6 (अप्रैल- सितंबर)
% परिवर्तन	17.4	-7	21.6	46.2	5.9	0.4	3.3^
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	210	201.2	263.8	334.3	326.7	285.4	151.6 (अप्रैल- सितंबर)
% परिवर्तन	22.2	-4.2	31.1	26.7	-2.3	-12.6	-0.7^
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	-118.4	-109.6	-118.7	-183.3	-190.3	-135.8	-72.7 (अप्रैल- सितंबर)
व्यापार जीडीपी (%)	39.9	34.2	36.3	42.3	42.6	40.7	-
निर्यात जीडीपी (%)	15.1	13.1	14.7	16.3	16.2	16.7	-
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)**	106.0	96.0	124.6	142.3	145.7	151.5	78.9 (अप्रैल- सितंबर)
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)**	46.3	49.7	53.1	62.2	65.9	69.5	17.5 (अप्रैल-जून)
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर) **	52.0	60.0	80.6	78.2	80.8	78.5	43.1 (अप्रैल- सितंबर)
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)**	54.0	36.0	44.0	64.1	64.9	73.0	35.9 (अप्रैल- सितंबर)
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-28.7	-38.4	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-7.8 (अप्रैल-जून)
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	-2.3	-2.8	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.7
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	252.0	279.1	304.8	294.4	292.0	304.2	276.3 (सितंबर 27,'13)
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	224.5	260.9	317.9	360.8	409.4	440.6	450.1 (अप्रैल-जून)
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.3	18.2	18.2	20.5	22.0	23.3	23.2 (अप्रैल-जून)
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	43.3	52.3	65.0	78.2	96.7	89.2	87.9 (अप्रैल-जून)
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	19.2	20.1	20.4	21.7	23.6	20.3	19.5 (अप्रैल-जून)
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	4.4	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	8.1 (अप्रैल-जून)
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	41.9	37.7	34.8	46.6	34.3	36.0	21.5 (अप्रैल- सितंबर)
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	1.2	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	-
एफआईआई (निवल) (बिलियन यूएस डॉलर)	-15.0	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	22.3 (अप्रैल-सितंबर)
एफडीआई प्रवाह (बिलियन यूएस डॉलर)	19.4	15.1	16.5	10.9	7.1	9.2	0.6 (अप्रैल- सितंबर)
मेमो मदें :	2009	2010	2011	2012	2013	2014[f]	2015[f]
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	-0.4	5.2	3.9	3.4	3.3	3.3	3.8
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-3.4	3.0	1.7	1.2	1.4	1.8	2.3
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	3.1	7.5	6.3	5.1	4.7	4.4	5.0
विश्व पण्य व्यापार(परिमाण,% परिवर्तन)	-11.7	14.0	6.6	2.7	2.7	3.8	5.1
विश्व पण्य निर्यात(ट्रिलियन यूएस डॉलर)	12.5	15.2	18.1	18.2	18.7	19.3	20.1
विश्व पण्य निर्यात मूल्य में वृद्धि(%)	-22.0	21.6	19.5	1.0	2.5	3.4	4.2

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक : केन्द्रीय बजट, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, मासिक बुलेटिन एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, वित्त मंत्रालय, सीएसओ, ईआईयू, नैस्कॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ), डब्ल्यूईओ, आईएमएफ.

टिप्पणी : भारत सरकार के अनुमान, पूर्वानुमान, **%** परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में है, - उपलब्ध नहीं, ***** - बजट 2014-15 अनुमान, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2014-15 में 5.4 से 5.9 प्रतिशत के दायरे में, ****** 2009-10 से आंकड़े आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़ों के मानक प्रस्तुतीकरण के नय फॉर्मेट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं.

चार्ट 1 : भारत का निर्यात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

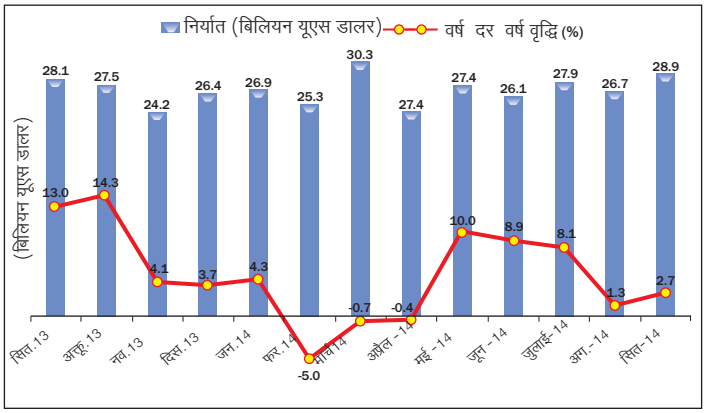

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 2 : भारत का आयात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

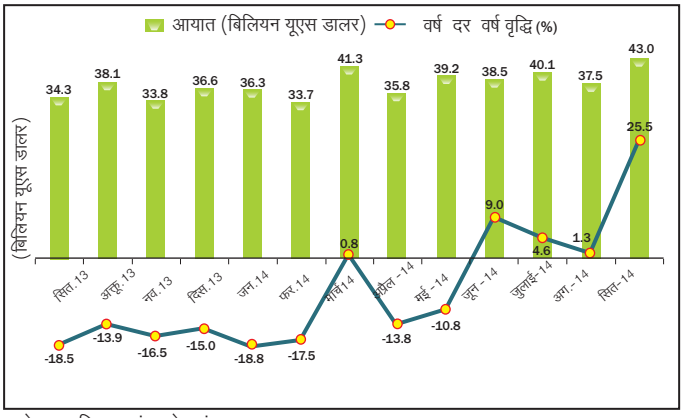

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3 : 2013-14 में भारत की निर्यात संरचना

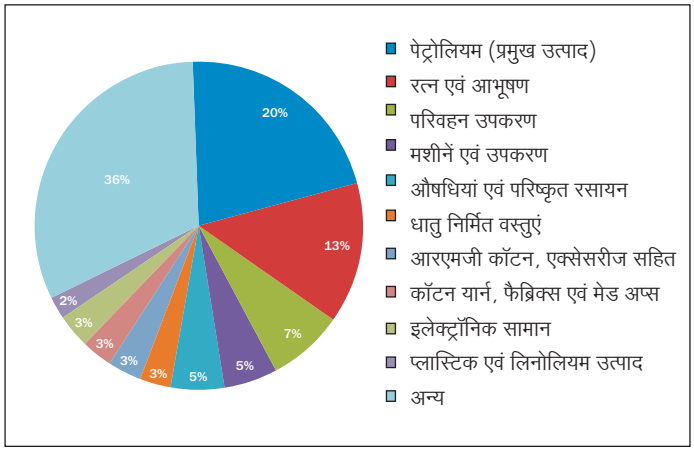

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 4 : 2013-14 में भारत की आयात संरचना

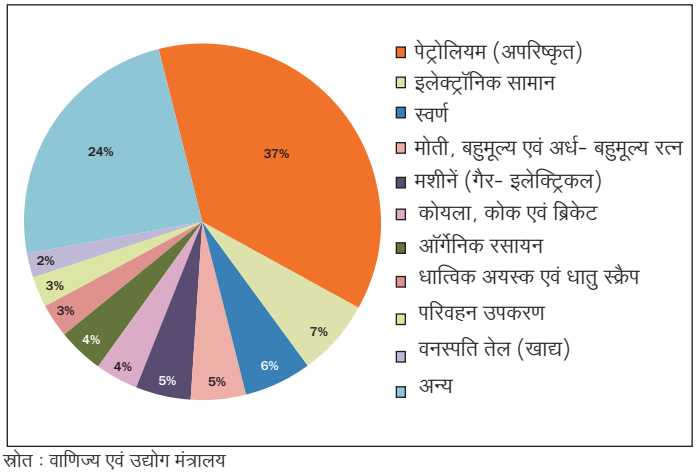

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 5 : विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा

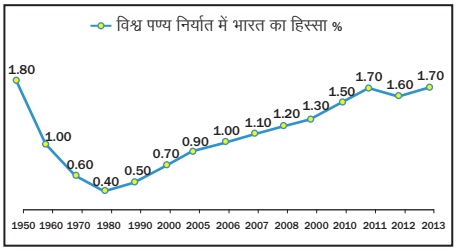

टिप्पणियां : 1) जर्मनी को प्रतिस्थापित करते हुए चीन 2009 में अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरा है. 2) भारत 2013 में 19वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा है जो 2007 के 26वें स्थान और 2000 के 32वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 सितंबर 2014 की स्थिति)

चार्ट 6 : विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा

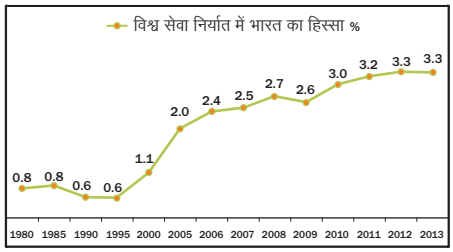

टिप्पणियां : 1) भारत वर्ष 2013 में छठा सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक बनकर उभरा है जो 2012 के 7वें स्थान और 2011 के 9वें स्थान, 2009 के 11वें स्थान और 2005 के 15वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 सितंबर 2014 की स्थिति)

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रमाणिक हैं। प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है.

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005
दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

व्यापार एवं साझेदारी अवसर

व्यापार अवसर

डेरी उपकरण एवं मशीनरी

डेयरी उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर डेरी उपकरण, स्टेनलेस स्टील के दूध के डब्बे, बाल्टी एवं बर्तन, भंडारण प्रणाली, डेरी उत्पाद मशीनरी तथा सोलर रेफ्रिजरेटर आदि जैसे उत्पादों को तैयार करने वाले विनिर्माता एवं निर्यातक द्वारा व्यापार अवसर.

ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े

जयपुर, राजस्थान के ब्लॉक प्रिंटिंग कारीगर रेडिमेड कपड़े एवं टेक्सटाइल उत्पादों को तैयार कर रहे हैं तथा पारंपरिक कला को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं. उत्पादों में कपड़े, स्कार्फ, बड़े झोले, स्कर्ट, शर्ट, बैग तथा पजामा आदि हैं.

औद्योगिक वस्तुएं

आई एस ओ 9001:2008 से प्रमाणित लिफ्टिंग उपकरणों के उत्पादक एवं निर्यातक द्वारा हर तरह के लिफ्टिंग जैसे चेन-पुली ब्लॉक, इलेक्ट्रिक वायर रोप हॉइस्ट, इलेक्ट्रिक चैन हॉइस्ट, ई ओ टी क्रेन, जिब क्रेन्स, गैन्ट्री क्रेन्स तथा लिंक चेन आदि की पेशकस.

स्टील उत्पाद

पूर्ण एकीकृत फ्लैट कार्बन स्टील मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र से फ्लैट उत्पादों का सबसे बड़ा भारतीय निर्यातक. प्री-पेंटेड कलईदार स्टील कॉइल, गर्म तथा ठंढे रोल्ड स्टील कॉइल तथा वायर रॉड आदि तैयार करने के लिए 20 से अधिक देशों में लौह अयस्क का निर्यातक.

पट्टचित्र पैंटिंग

कपड़े पर उकेरी जानेवाली ओडिसा की पारंपरिक स्क्रोल पेंटिंग जो हिन्दू पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं. इन पेंटिंगों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है तथा इसे कुशल पेंटरों द्वारा तैयार किया जाता है.

ऑटोमोबाइल पार्ट

भारत के अग्रणी ओरिजनल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) द्वारा विभिन्न उत्पादों जैसे ई पी डी एम रबड़, पी वी सी, नाइट्राइल, डोर सील, विंडो चैनल, टी पी ई सीलिंग उत्पाद तथा रेडिएटर होजेस आदि की पेशकस.

निवेश अवसर

भारतीय कंपनियों के लिए साझेदारी के अवसर

मोज़ाम्बिक की एक कंपनी कच्चे माल जैसे नाइट्रिक एसिड तथा खाद जैसे अमोनियम नाइट्रेट, एन पी के तथा डी ए पी आदि के उत्पादन हेतु एक औद्योगिक खाद संयंत्र लगाने के लिए ई पी सी, तकनीकी आपूर्तिकर्ता और/ अथवा ईक्विटी निवेशक के साथ साझेदारी करने के लिए इच्छुक भारतीय कंपनियों की तलाश कर रही है. दूसरे चरण में, कंपनी का लक्ष्य अमोनिया, यूरिया एवं नाइट्रोजन का उत्पादन बढ़ाने तथा मोज़ाम्बिक में बिजली उत्पादन हेतु 220 मेगावाट के को-जेनरेशन विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य है.

साझेदारी का स्वरूप : स्ट्रेटेजिक लोकेशन का लाभ उठाकर एशियाई बाजार एवं पड़ोसी अफ्रीकी देशों को निर्यात करना.
इच्छुक कंपनियां / व्यक्ति विपणन सलाहकारी समूह से नीचे दिए गए संपर्क विवरण के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें- फोन: +91-22- 2217 2600 एक्सटेंशन: 2737 / 2707; फैक्स: +91-22-2218 8268. ई-मेल: mas@eximbankindia.in